



बीजेपी को विदेशी साजिश की आशंका, सांसद ने जेपीसी चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा- जांच की जाए

# वक्फ बिल पर कहां से आ गए 1.25 करोड़ फीडबैक !

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने सभी से राय मांगी तो करीब सवा करोड़ फीडबैक मिल गए। अब भाजपा को लग रहा है कि इसके पीछे विदेशी ताकतों की साजिश है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विदेशी संस्थाओं और कट्टरपंथी संगठनों के संभावित प्रभाव की आशंका जताई है। उन्होंने गृह मंत्रालय के नेतृत्व में एक व्यापक जांच की भी मांग की है ताकि पता चल सके कि इतने सारे फीडबैक कहां से आए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के लिए पिछले सत्र में लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश किया था। विपक्ष ने विधेयक को जेपीसी में भेजने की मांगी की और अब यह वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी के पास है। निशिकांत दुबे जेपीसी के सदस्यों में शामिल हैं। उन्होंने जेपीसी अध्यक्ष जगदीशका पाल को एक पत्र लिखकर संदेह व्यक्त किया कि इतनी बड़ी संख्या में फीडबैक केवल भारत के भीतर से ही स्वाभाविक रूप से नहीं आ सकता है। उन्होंने बताया कि कई फीडबैक की भाषा मिलती-जुलती है जिससे साजिश की बू आ रही है। दुबे ने कहा, सबसे बड़ा यह है कि इनमें से कितने सुझाव भारत के भीतर से और कितने विदेश से आए।

## जिह्वादी, कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों की साजिश?

दुबे ने विशेष रूप से जाकिर नाइक जैसे व्यक्तियों और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों के साथ-साथ पाकिस्तान की आईएसआई और चीन समेत कुछ विदेशी खुफिया एजेंसियों का नाम लिया, जो भारतीय लोकतंत्र को अस्थिर करने में जुटी रहती हैं। उन्होंने विधायी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा के लिए फीडबैक की जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दुबे ने जोर देकर कहा, ये फीडबैक कहां से आए, इसकी सावधानीपूर्वक जांच किया ही जाना चाहिए। हम विदेशी ताकतों को संभावित एजेंडे पर आधारित इन्पुट के जरिए हमारी विधायी समितियों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दे सकते।

## किरेन रिजिजू ने भी जताई चिंता



संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इन्हीं चिंताओं को दोहराया और कहा कि इतनी भारी संख्या में मिले फीडबैक सामान्य स्थिति को तो नहीं दर्शाते। उन्होंने कहा कि पहले तो 1,000 फीडबैक आ जाएं तो भी बहुत माने जाते थे। रिजिजू ने प्रक्रिया में पारदर्शिता के महत्व पर जोर देते हुए कहा, किसी ने कभी नहीं सोचा था कि जेपीसी को करोड़ों की सिफारिशें मिलेंगी।

## ओवैसी ने मांग लिए सबूत

बीजेपी की तरफ से उठी जांच की मांग के जवाब में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी को जाकिर नाइक, आईएसआई और चीन को फीडबैक सबमिशन से जोड़ने वाले ठोस सबूत पेश करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर चीन इसमें शामिल है, तो क्या चीन भारत में रजिस्ट्रेशन कर सकता है? क्या आप लोगों के पास कोई सबूत है कि आईएसआई, चीन और जाकिर

नाइक वक्फ में शामिल हैं? ओवैसी ने आरोपों पर स्पष्टता की मांग करते हुए सवाल किया।

## जेपीसी के पास वक्फ अमेंडमेंट बिल

9 अगस्त, 2024 को गठित जेपीसी में 31 सदस्य हैं। इनमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा के सांसद हैं। इन पर वक्फ विधेयक में संभावित संशोधनों पर रायशुमारी के साथ एक निष्कर्ष पर पहुंचने की जिम्मेदारी है। इसी वजह से समिति ने विभिन्न समूहों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए थे, लेकिन इतनी भारी संख्या में मिले फीडबैक ने प्रक्रिया को और जटिल कर दिया है। बीजेपी को लगता है कि यह बिना साजिश के नहीं हो सकता। सवाल है कि क्या अपने ही सांसदों की मांग पर सरकार जांच करवाएगी?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जमीन पर उतरकर बनाए सदस्य, प्रदेश प्रभारी बोले- हर दल के सदस्यों का बीजेपी में स्वागत

# लोगों के पास पैदल पहुंचे सीएम, मोबाइल लेकर अपलोड की जानकारी



कम 100-100 सदस्य बनाए जाएंगे।

मिस कॉल से अधिक ऑर्थेंटिक दूसरा कुछ नहीं बाजेपी के प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने कहा कि- ठेला-कबाड़ी वाले सबको सदस्य बनाएंगे। कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, मिस कॉल के बाद सदस्य बनने और ओटीपी आता है, इससे अधिक ऑर्थेंटिक और कुछ नहीं हो सकता है। कांग्रेस के अंदर जो फजीवांडा चलता है, कांग्रेस को दूसरों में भी वही दिखता है। ठेला वाले, कबाड़ी वाले सबको सदस्य बनाया जा रहा है।

हम सदस्यता का नया रिकॉर्ड बनाएंगे मीडिया से बात करते हुए सीएम यादव ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में उत्साह और उमंग

दिखाई दे रहा है वो ये दिखता है कि भाजपा के प्रति जनता में कितना प्रेम और विश्वास है, उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि आज शाम तक हम सदस्यता का नया रिकॉर्ड बनायेंगे **जम्मू कश्मीर में भाजपा की बनेगी सरकार** जम्मू कश्मीर में आज हो रही वोटिंग के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 साल बाद वहां चुनाव हो रहे हैं मैंने खुद देखा है कि 370 हटने के बाद पूरी घाटी में वहां अब एक नया अनुकूल वातावरण बन रहा है, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है हम तो चाहते हैं भाजपा का कार्य क्षेत्र बढे, मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी।

## जम्मू-कश्मीर चुनाव - 25 लाख से अधिक मतदाताओं ने ईवीएम में बंद किया 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला

## दूसरे चरण में श्री माता वैष्णो देवी सीट पर सबसे ज्यादा मतदान

जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान बुधवार शाम खत्म हो गया। दूसरे दौर में छह जिलों की कुल 26 सीटों के लिए मतदान कराया गया। इस चरण में 25 लाख से अधिक मतदाता 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। दूसरे दौर में श्रीनगर जिले की आठ सीटों पर मतदान हुआ। इसके बाद रियासी में छह, बडगाम में पांच, रियासी और पुंछ में तीन-तीन और गांदरबल में दो सीटों पर मतदान कराया गया। शाम 5 बजे तक जम्मू कश्मीर में 54.00 फीसदी मतदान हुआ। सबसे ज्यादा



71.81 फीसदी वोटिंग रियासी जिले में तो सबसे कम श्रीनगर जिले में 27.31 फीसदी दर्ज की गई। दूसरे चरण में रियासी जिले की श्री माता वैष्णो देवी सीट पर सबसे ज्यादा 75.29 फीसदी मतदान हुआ है। हालांकि, आंकड़ों

में बदलाव संभव है। इससे पहले 18 सितंबर को हुए पहले चरण में 61.38 फीसदी मतदान हुआ था। सबसे ज्यादा 80.20 फीसदी वोटिंग किरतवाड़ जिले में तो सबसे कम पुलवामा जिले में 46.99 फीसदी दर्ज की गई थी।

## 15 देशों के राजनयिकों ने जम्मू-कश्मीर जाकर देखी वोटिंग प्रक्रिया

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर तीन चरणों में कराए जा रहे चुनावों को देखने के लिए बुधवार को अमेरिका, नॉर्वे और सिंगापुर समेत 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिकों ने यहां का दौरा कर चुनावी प्रक्रिया देखी। इस हाई लेवल डेलीगेशन में अमेरिका, मैक्सिको, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस के दिल्ली स्थित दूतावासों के राजनयिक शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि वरिष्ठ राजनयिकों के इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने घाटी में पहुंचने के तुरंत बाद बडगाम जिले के ओमपोरा में मतदान केंद्रों का दौरा किया। इसके बाद डेलीगेशन लाल बाग निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत चिनार बाग में अमीरा कदल और एसपी कॉलेज में प्रतिनिधिमंडल को पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किए गए विशेष पिक पोलिंग स्टेशन को देखने का भी मौका मिला। इस चुनावी मतदान केंद्र का संचालन पूरी तरह से महिलाएं कर रही हैं। पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद चुनाव अधिकारियों ने डेलीगेशन को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के उभरने के बाद संभवतः यह पहली बार है। जब विदेशी पर्यवेक्षकों को चुनाव देखने की अनुमति दी गई है। केंद्र ने इस साल के शुरू में हुए लोकसभा चुनावों के बाद अच्छे मतदान प्रतिशत को देखते हुए विदेशी प्रतिनिधियों को शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया दिखाने के उद्देश्य से आमंत्रित किया था। जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को वोट डल चुके हैं। दूसरे चरण में 26 सीटों के लिए बुधवार को वोट डाले गए। तीसरे चरण में 40 सीटों के लिए एक अक्टूबर को मतदान होगा। तीनों चरणों में डाली गई वोटों की गिनती आठ अक्टूबर को होगी।

# भारत के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं बता सकते

सीजेआई की कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को खरी-खरी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जस्टिस की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चलने वाली कार्रवाई को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि भारत के किसी भी हिस्से को कोई भी पाकिस्तान की तरह नहीं बता सकता है। जजों को ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी से परहेज करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने कहा है कि आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस वी. श्रीशेषानंद ने अपनी टिप्पणियों के लिए ओपन कोर्ट में 21 सितंबर को माफी मांग ली थी और ऐसे में हम कार्यवाही बंद करते हैं। अदालती कार्यवाही के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने कथित तौर पर एक महिला वकील के खिलाफ टिप्पणी और फिर



एक अन्य मामले में कार्यवाही के दौरान बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को खुद से संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट के जस्टिस ने मकान मालिक-किरायेदार विवाद से जुड़े एक अन्य मामले में

बेंगलुरु में मुस्लिम बहुल एक इलाके को 'पाकिस्तान' बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को न्यायिक प्रक्रिया के दौरा किसी भी ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी से बचना चाहिए। उन्हें ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। ऐसी टिप्पणियां जिससे महिला के प्रति पूर्वाग्रह दिखे या फिर किसी समाज

के किसी वर्ग के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए को पूर्वाग्रह वाला हो।

**मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहने पर विवाद** कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई के वीडियो में एक जगह जस्टिस ने बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल एक इलाके को पाकिस्तान कहा था और एक अन्य वीडियो में जस्टिस ने महिला वकील के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वह मामला वैवाहिक विवाद से संबंधित था। शीर्ष अदालत ने कहा कि सुनवाई के दौरान लापरवाही से हुई कोई भी टिप्पणी पूर्वाग्रह वाली हो सकती है। अदालती कार्रवाई के दौरान जज को इस बात को लेकर सजग रहना होगा कि वह कोई भी ऐसा कॉमेंट ना करे जो महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह वाला हो या फिर समाज के किसी वर्ग के खिलाफ पूर्वाग्रह वाला हो।

## भारत के बजाय यूके ने आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुनाव

# ऑस्कर की दौड़ में शामिल हुई एक और हिंदी फिल्म 'संतोष'

नई दिल्ली। 'लापता लेडीज' के बाद एक और हिंदी फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है। फिल्म का नाम है 'संतोष'। हिंदी फिल्म को सुनकर अगर आप यह सोच रहे हैं कि इसे भारत की तरफ से प्रतिष्ठित अवॉर्ड में भेजा जा रहा है तो ऐसा नहीं है। इस फिल्म को यूके ने आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना है। शाहना गोस्वामी और

सुनीता राजवार अभिनीत हिंदी फिल्म संतोष को ऑस्कर 2025 के लिए यूके की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। दो दिन पहले ही किरण राव के निर्देशन में बनी हिंदी फिल्म लापता लेडीज को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत की तरफ से ऑस्कर में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा है। अब एक और हिंदी फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हो गई



है। **इस श्रेणी के लिए चुनी गई है फिल्म** फिल्म संतोष को यूके की तरफ से 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की रेस में शामिल किया गया है। डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को बाफ्टा ने चुना था। यह ऑर्गनाइजेशन अमेरिकन एकेडमी की तरफ से नियुक्त है। इस समीक्षा को यूके की तरफ से प्रविष्टि को

सबमिट किए जाने के लिए नियुक्त किया गया है। **ब्रिटेन में व्यापक स्तर पर हुई रिलीज** फिल्म संतोष का प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में भी हो चुका है। संतोष फिल्म को ब्रिटेन में व्यापक स्तर पर रिलीज किया गया था। इस फिल्म का निर्देशन संस्था सूरि ने किया है। इसे बनाने में ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स का भी काफी सहयोग रहा है।



तिरुपति बालाजी के प्रसाद के मुद्दे पर निकाला मार्च, साधु-संतों समेत कई संगठन हुए शामिल

# हिन्दू समाज का अपमान, न सहेगा हिंदुस्तान....

इंदौर। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट के विरोध में बुधवार को इंदौर के व्यंकटेश देव स्थान से बड़ी मार्च निकला। जिसमें हजारों की संख्या में साधु संत, सामाजिक संगठन व हिन्दू संगठनों ने भाग लिया। शाम चार निकले शांति मार्च निकाला गया। जिसमें रामानुजाचार्य नागोरिया पीठाधीश्वर स्वामी विष्णु

प्रपन्नाचार्य महाराज भी शामिल हुए। व्यंकटेशन देव स्थान से बुधवार शाम को मार्च निकाला। जिसमें बटुक आगे भगवा पताकाएं लेकर चल रहे थे। इसके बाद शामिल लोग हिन्दू समाज का अपमान, न सहेगा हिन्दूस्तान, मिलावट करने वालों को कड़ा दंड मिले जैसे नारे लगाए गए। ज्ञापन सौंप कर कहा गया कि दोषियों को



चिन्हित कर कठोर दंड दिया जाए और धर्मस्थलों की व्यवस्था में प्रशासनिक दखलंदाजी बंद की जाए। हमारी मांग है कि सरकार को धार्मिक देवस्थानों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रोकना पड़ा ट्रैफिक शांति मार्च में इतनी भीड़ शामिल हुई कि महुनाका, मोती तबेला का ट्रैफिक रोकना पड़ा। मार्च में

वीर बगीची के पवनानंद महाराज, दत्त माउली संस्थान के अण्णा महाराज, अन्नपूर्णा आश्रम के संत जयेंद्रानंद महाराज, श्री रणजीत हनुमान मंदिर के पंडित दीपेश व्यास, खजराना गणेश मंदिर के पंडित अशोक भट्ट, हंस दास मठ के पवन शर्मा, गजासीन शनि मंदिर के संत दादू महाराज के साथ ही अनेक संत-महंत मौजूद रहे।

## इस साल पूरा होना था इंदौर-बुधनी रेल लाइन का काम, अब हुई शुरुआत

इंदौर। इंदौर-बुधनी रेल परियोजना काम अब तेज होने की उम्मीद है। हाल ही में इसके टेंडर जारी हुए हैं। पांच साल पहले इस परियोजना को मंजूरी मिली थी,लेकिन जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का पुरजोर विरोध रहा। इस कारण काम गति नहीं पकड़ पाया। वर्ष 2024 तक काम पूरा हो जाना था, लेकिन अब जाकर निर्माण ने गति पकड़ी है। बजट में मध्य प्रदेश के रेल प्रोजेक्टो में सबसे ज्यादा राशि 1100 करोड़ रुपये इस परियोजना को मिले है। परियोजना के लिए अभी भी जमीन अधिग्रहण का काम पूरा नहीं पाया है। देरी के कारण लागत भी बढ़ी है। इस परियोजना के बनने से जबलपुर और इंदौर के बीच की दूरी 150 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। दोनों शहरों के बीच सफर करने में महज 5 से 6 घंटे का समय लगेगा. यह काम पश्चिम मध्य रेलवे



जबलपुर के द्वारा किया जाएगा जिसका सर्वे भी पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत दस से ज्यादा बड़े औ चालीस से ज्यादा छोटे पुल-पुलिया बनाए जाएंगे। कुछ नए स्टेशन भी बनेंगे। जिसके लिए ज्यादा जमीन आ रही है।जबलपुर से गाडरवारा, बुधनी होते हुए इंदौर तक नई रेल लाइन बिछाई जानी है। इसके लिए 342 किलोमीटर लंबे ट्रेक तैयार होंगे। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रेलवे किसानों से

जमीन भी अधिग्रहण कर रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के सीपीआरओ हर्ष श्रीवास्तव का कहना है कि रेल लाइन पर भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है लेकिन भूमि के बदले नौकरी को कोई भी योजना नहीं है।किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इस रेल लाइन के बन जाने से जबलपुर से गाडरवारा होते हुए बुधनी से इंदौर का सफर किया जा सकेगा।

## राऊ विधायक मधु वर्मा की हालत में सुधार

बायपास सर्जरी होगी, मंत्री विजयवर्गीय, पीसीसी चीफ मिलने पहुंचे

इंदौर। राजू विधानसभा से विधायक मधु वर्मा की हालत में 24 घंटे बाद सुधार आया है। उन्हें हार्ट में ब्लॉकेज पाए गए हैं जिसके लिए सर्जरी करनी होगी। विधायक वर्मा को देखने आज सुबह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और संभागायुक्त दीपक सिंह पहुंचे। विशेष जुपिटर अस्पताल के एमडी डॉ. राजेश कासलीवाल ने बुधवार

दोपहर मीडिया को बताया कि कल जब विधायक मधु वर्मा को अस्पताल लाए थे तब हालत नाजुक थी। लेकिन अब पहले से काफी बेहतर हैं। उन्हें एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज मिला है। इसके लिए बाद में बायपास सर्जरी करना पड़ेगी। मेडिकली फिट होने में एक-दो दिन का समय लगेगा। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया बायपास सर्जरी इंदौर में होगी या

बाहर, यह अभी तय होना शेष है। परिवार और करीबी नेताओं से इस पर चर्चा चल रही है। भाजपा विधायक मधु वर्मा को मंगलवार सुबह हार्ट अटैक आया था। उन्हें तत्काल विशेष जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही थी। उन्हें 48 घंटे के लिए डॉक्टर की निगरानी में रखा गया। अब सुधार हुआ है।

## एसीपी ने मदद के बहाने महिला से बढ़ाई नजदीकियां पति ने खोली पोल, सीएम तक पहुंची शिकायत

इंदौर। इंदौर में एक एसीपी पर एक महिला को आपत्तिजनक मैसेज भेजने और उससे नजदीकियां बढ़ाने के गंभीर आरोप लगे हैं। महिला अपने पति के साथ विवाद को सुलझाने के लिए एसीपी के पास मदद मांगने गई थी, लेकिन एसीपी ने इस मौके का गलत फायदा उठाते हुए महिला को सोशल मीडिया और वॉट्सऐप के जरिए आपत्तिजनक मैसेज और हीरो-हिरोइन के वीडियो भेजने शुरू कर दिए। महिला के पति को जब इस बात का शक हुआ, तो उसने अपनी पत्नी और एसीपी के बीच हुई वॉट्सऐप चैट को निकाला और इंदौर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच तत्कालीन डीसीपी आदित्य मिश्रा को सौंपी थी। जांच में देरी होती देख पति ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। पति का आरोप है कि एसीपी ने महिला को कई बार गुप्त मीटिंग्स की तस्वीरें और जानकारीयां भी भेजीं। पति ने यह भी कहा कि एसीपी की इन हरकतों के बारे में उनके परिवार को बताया जाना चाहिए। **पति को दी धमकियां** सुखलिया इलाके की एक महिला अपने पति के साथ चल रहे आपसी विवाद को लेकर एसीपी के पास मदद मांगने गई थी। महिला का आरोप है

कि एसीपी ने मदद करने के बहाने उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। इसके साथ ही एसीपी ने उसे कई बार लव इमोजी भेजीं और उसके पति को हवालात में बंद करने की धमकी भी दी। पति ने गृह मंत्रालय, डीजीपी और इंदौर पुलिस कमिश्नर को एसीपी के खिलाफ सबूतों के साथ शिकायत दी। जांच अधिकारी ने महिला का बयान बंद कमरे में लिया, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। **थाने बुलाकर डांटा** पीड़ित पति ने आरोप लगाया कि एसीपी ने उसे कई बार थाने बुलाकर डांट-फटकार लगाई और कई बार जबरन थाने में बिठाए रखा। जब पति को अपनी पत्नी और एसीपी की मिलीभगत का शक हुआ, तो उसने पत्नी के मोबाइल को वॉट्सऐप चैट को हिस्ट्री निकाली, जिससे दोनों के बीच की बातचीत का खुलासा हुआ। पति ने यह चैट पुलिस को सौंपी है। **गोपनीय जानकारी का खुलासा** पति ने अपनी शिकायत में बताया कि एसीपी ने महिला के साथ गोपनीय जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि एसीपी ने अपनी व्यस्तता दिखाने के लिए महिला के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री की इंदौर यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल ड्यूटी का टाइम टेबल शेयर

किया। इसके अलावा, डीआईजी ऑफिस में आयोजित एक गोपनीय मीटिंग की तस्वीरें और मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना से जुड़े दस्तावेज भी महिला को भेजे गए। यह मामला मध्यप्रदेश पुलिस रेगुलेशन और मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के खिलाफ जाता है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी ने अपने पद और अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। मामले की शिकायत तत्कालीन पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को की गई थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। **राज्य की सुरक्षा को खतरा** हाईकोर्ट एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे ने कहा कि महिलाओं से अमर्यादित वॉट्सऐप चैटिंग करने वाले ऐसे अधिकारी से कोई भी दुश्मन देश आसानी से हनीट्रेप के जरिए गोपनीय जानकारी प्राप्त कर सकता है। ऐसे अफसरों से राज्य की आंतरिक सुरक्षा पर खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं इंदौर के पूर्व पुलिस कमिश्नर मकरंद देऊस्कर ने कहा कि पीड़िता के पति ने इस तरह की शिकायत की थी। मामला गंभीर था। उस समय जौन-1 के डीसीपी आदित्य मिश्रा को जांच सौंपी गई थी। मेरे ट्रांसफर के कुछ समय पहले ही वह केस मिला था लेकिन ट्रांसफर होने के बाद जांच कहा है पता नहीं।

## खुद का अपहरण करवाने वाली नीट की छात्रा पर केस दर्ज, पिता से मांगे थे 30 लाख

इंदौर। नीट की तैयारी कर रही छात्रा काव्या ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी और अपने परिवार से 30 लाख रुपये की फिरीती मांगी। इस मामले में पुलिस ने काव्या और उसके दो दोस्तों हर्षित यादव और ब्रजेन्द्र प्रताप अहिरवार को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। इस झूठी अपहरण की साजिश के कारण राजस्थान, शिवपुरी और इंदौर की पुलिस 15 दिनों तक परेशान रही। करीब पांच महीने बाद इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। भंवरकुआ पुलिस के अनुसार, काव्या और उसके दोस्तों ने मिलकर अपहरण की यह झूठी साजिश रची थी। पुलिस को सबसे पहले कोटा के विज्ञान नगर थाने से काव्या के अपहरण की सूचना मिली थी। काव्या के पिता रघुवीर धाकड़ ने शिकायत की थी कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है और अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपये की फिरीती की मांग की है। अपहरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जयपुर और कोटा में काव्या की तलाश शुरू



की। कई दिनों की खोजबीन के बाद पुलिस को पता चला कि यह अपहरण का मामला नहीं है, बल्कि काव्या ने खुद अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी। उसने अपनी मर्जी से अपने हाथ-पैर बंधवाकर तस्वीरें खिंचवाई और इन्हें अपने माता-पिता को भेज दिया। इन तस्वीरों में काव्या के चेहरे पर खून के निशान भी नजर आ रहे थे। इसके बाद फिरीती की रकम के साथ बैंक खाते की जानकारी भी दी गई थी। **पुलिस की कार्रवाई** काव्या और उसके दोस्त हर्षित को 18 मार्च 2024 को लापता होने की सूचना मिली थी। उन्हें 15 दिन बाद इंदौर

में उसकी सहेली के घर से बरामद किया गया। यह घर इंदौर के देवगुण्डिया इलाके के पास इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के पास स्थित था। उस समय उन्हें कोटा पुलिस को सौंप दिया गया था, जिन्होंने जांच के बाद मामला इंदौर की भंवरकुआ पुलिस को फिर से सौंप दिया। इंदौर पुलिस ने अब इस मामले में नए सबूतों के आधार पर कार्रवाई की है। **अपहरण की झूठी कहानी** काव्या को नीट की तैयारी के लिए उसके परिजनों ने कोटा भेजा था। 18 मार्च को काव्या के पिता रघुवीर धाकड़ को एक मैसेज आया जिसमें दावा किया गया था

# भरे बाजार ब्रा पहन निकली लड़की, वीडियो वायरल

लड़की बोली- जिन्हें दिक्कत उन्हें मेरा एड्रेस दें

शहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें रील शूट करने के लिए एक लड़की भरे बाजार ब्रा पहनकर घूम रही है। बताया जा रहा है कि यह लड़की बीते तीन दिनों से लगातार शहर के प्रमुख जगहों का वीडियो शेयर कर रही है। इसमें एक वीडियो इंदौर के चर्चित छप्पन दुकान का

भी बताया जा रहा है। वायरल वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। इन्हीं में से कुछ लोगों ने जब संस्कार सीखने की बात कह कर लड़की की आलोचना की तो उसने पलटवार करते हुए कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको दिक्कत है वे मुझसे मिल सकते हैं। आपमें से जिसके भी किसी फैमली मेंबर या रिश्तेदार ने मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है, कृपया उन्हें मेरा एड्रेस बता दें।

मंत्री विजयवर्गीय बोले- यह फंडामेंटल राइट्स का दुरुपयोग वायरल वीडियो पर एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह मामला मेरे भी संज्ञान में आया है। इसके खिलाफ कुछ महिला संगठन पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देंगी। इंदौर सांस्कृतिक विरासत का शहर है। इंदौर में इस तरह की अभद्रता का स्थान नहीं होना चाहिए। सभी को पहनने, खाने, पीने की छूट है, लेकिन यह फंडामेंटल राइट्स का

दुरुपयोग है। प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। उधर, पुलिस ने कहा- एक लड़की का अश्लील वीडियो वायरल होने को जानकारी लगी है। कुछ संगठनों ने भी ज्ञापन दिया है और लड़की के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। **यह कहा लड़की ने** लड़की ने कहा- मैं मानती हूँ कि वो नॉर्मल नहीं थे लेकिन ऐसे ही कपड़े बहुत सी लड़कियां पहनती

हैं। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। मैं दिखने में ऐसी ही लगती हूँ तो मैंने वह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। लड़की ने आगे कहा- मैं न्यूज में इसलिए आ रही हूँ क्योंकि लोगों को व्यूज की जरूरत है। मुझे लगता है कि मैं 100 दो सौ चैनलों पर अभी और आजंगी। मैं एक हफ्ते तक आती रहूंगी और इसी तरह ट्रेंडिंग बनी रहूंगी। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग मुझसे आकर मिल सकते हैं।





सदस्य यूजीसी की गाइड लाइन के आधार पर निजी विश्वविद्यालयों में करेंगे कुलपति की नियुक्ति

# कुलपति की नियुक्ति का निर्णय लेगी सर्व कमेटी

**भोपाल।** मध्य प्रदेश में 32 निजी विश्वविद्यालय में कुलपति (चीसी) की नियुक्ति के लिए सर्व कमेटी बनाई जाएगी। इनमें से आठ विवि के कुलपति भोपाल से हैं। मप्र निजी विवि विनियामक आयोग के अनुसार, कुलपति के चयन के लिए बनाई जाने वाली सर्व कमेटी में तीन सदस्य शामिल होंगे। सदस्य द्वारा यूजीसी की गाइड लाइन के आधार पर विवि में कुलपति की नियुक्ति की जाएगी। वहीं, अभी प्रभारी कुलपति को नियुक्ति किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के विनियमों एवं मप्र निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007, संशोधित 2013 एवं 2016 के धारा-17 के प्रविधानों के अनुसार तथा विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 99वां बैठक में पारित परिनियम-1 के अनुसार कुलगुरु की योग्यता और मापदंड के आधार पर निजी विवि में कुलगुरु की नियुक्ति के स्पष्ट प्रविधान हैं। परीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया गया कि अधिनियम की धारा 17



के अंतर्गत कुलगुरु की नियुक्ति के वर्णित प्रविधानों का पालन नहीं किया गया है। विवि में कुलगुरु की नियुक्ति अधिनियम की धारा 17 (1) के विपरीत की गई है, जो मापदंडों के अनुरूप नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। मप्र निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007, यथा संशोधित की धारा 17 (1) के प्रविधानों के विपरीत की गई। कुलगुरु की नियुक्ति आयोग अधिनियम की धारा-36 (10) (घ) के प्रविधान अंतर्गत अमान्य की जाती है। कुलगुरु को तत्काल हटाते हुए विश्वविद्यालय परिनियम के युक्त प्रविधानों के

अंतर्गत कार्यवाहक कुलगुरु की तत्काल नियुक्ति योग्यता एवं मापदंड अनुसार करना सुनिश्चित करें। कुलगुरु की नियुक्ति के लिए 15 दिन में कार्रवाई के लिए कहा गया है।

**गाइड लाइन के आधार पर नियुक्ति होगी**—यूजीसी की गाइड लाइन के आधार पर ही कुलपति की नियुक्ति होगी। इसके लिए सर्व कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें तीन सदस्य शामिल होंगे। इसके द्वारा लिए गए निर्णय पर कुलपति को नियुक्त किया जाएगा। – प्रो. भरत शरण सिंह, चेयरमैन, मप्र निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

## सियार को पकड़ने के लिए तीन पिंजरे रखे गए पर अभी तक एक भी नहीं फंसा फिर खुला बोरवन पार्क एक घंटे की मिली छूट

**भोपाल।** संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में स्थित बोरवन पार्क का सन्नाटा आखिरकार मंगलवार को टूट गया। सियार दिखने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से इस पार्क को करीब दो हफ्ते पहले बंद कर दिया गया था। अभी इसे दिन में एक घंटे के लिए खोलने की छूट दी गई है। वन विभाग ने मॉर्निंग वाक करने आ रहे लोगों के आग्रह पर सुबह सात से आठ बजे तक पार्क खोला है। हालांकि पार्क में सियार को पकड़ने के लिए तीन पिंजरे रखे गए हैं, पर अभी तक एक भी सियार नहीं फंसा है। शुरुआत में पिंजरे में श्वान और जंगली बिल्ले फंसे थे। अब कोई नव्य जीव पिंजरे के निकट भी नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही पार्क पहले की तरह सुबह एवं शाम के समय तीन-तीन घंटे खुलने लगेगा। इस बीच वन विभाग ने सियार पकड़ने के लिए तीसरा पिंजरा भी रख दिया है। बड़ी झील के किनारे विकसित इस पार्क में बड़ी संख्या में युवा सैर करने पहुंचते हैं। सुबह



के समय महिलाएं एवं बच्चे भी वाक करने आते हैं। बड़ी झील से सटे क्षेत्र में हाल ही में बोरवन क्लब ने सघन पौधारोपण किया था। यह पौधे अब वृक्ष का रूप ले रहे हैं। हरे भरे पेड़ों के बीच सैर करने का अपना ही आनंद है, यही कारण है कई बुजुर्ग भी स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से यहां पहुंचते हैं। 13 दिन से पार्क बंद होने से नियमित रूप से यहां आने वाले परेशान हो गए थे।

**किड्स जोन पहुंचे कुछ बच्चे**— पार्क में सियार दिखने के बाद इसे बंद किया गया था। यहां पहले से रखे दो पिंजरों में सियार

के बजाय श्वान, नेवले एवं जंगली बिल्ले फंसे थे। पार्क के एक हिस्से में बच्चों की सुविधा के लिए किड्स जोन बना है। यहां झूले, फिसलपट्टियां एवं बेंच आदि लगाई गई हैं। बच्चों के लिए यह एंटरटेनमेंट जोन बन चुका है। पार्क बंद होने से बच्चे भी परेशान थे, अब कुछ रौनक लौटी है। नागरिकों की मांग पर पार्क सुबह सात से आठ बजे तक एक घंटे तक खुला रहेगा। वनरक्षक डीपन तिवारी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से अभी पार्क को पूरा दिन खोलने का निर्णय नहीं हुआ है।

## 50 हजार रुपए में उसका सौदा कर जबरन करा दी थी शादी काम के बहाने महिला को राजस्थान ले जाकर बेचा, चार गिरफ्तार

**भोपाल।** शहर के हबीबगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 25 वर्षीय शादीशुदा महिला को राजस्थान ले जाकर बेचने का मामला सामने आया है। उसे साथ में काम करने वाली दो महिलाएं समेत चार लोग राजस्थान ले गए और वहां एक युवक से 50 हजार रुपये में सौदा कर बेच दिया। पुलिस ने महिला को अभिरक्षा में लेकर खरीदार समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ अपहरण और मानव तस्करी तथा खरीदार के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक इलाके में रहने वाली महिला शादी, पार्टी में खाना बनाने का काम करती है। उसके साथ छाया देशमुख, पूजा धनक और संतोष अशु उमका पति मनोज भालेराव काम करते थे। बीती फरवरी में इन्होंने महिला को बताया कि राजस्थान में काम करने चलना है। महिला उनके साथ काम



के लिए चली गई। वहां ले जाकर चारों ने उसे राजस्थान के राजसमंद में देवीलाल गर्ग नामक युवक से जबरन शादी करवा दी। इसके बदले चारों ने देवीलाल से 50 हजार रुपये की राशि ले ली। महिला से शादी करने के बाद देवीलाल ने उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। इधर, कई दिन तक महिला घर

नहीं लौटी तो उसकी मां ने थाने जाकर गुमशुदगी दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने लापता महिला को राजस्थान से दस्तयाब कर लिया। पीड़िता के बयान लेने के बाद पुलिस ने देवीलाल, छाया, संतोष और पूजा को गिरफ्तार कर लिया है। संतोष का पति मनोज फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

## निकायों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विभाग ने 30 प्रतिशत तक अवैध निर्माण को वैध कराने की सुविधा देने का भेजा प्रस्ताव निर्माण को वैध कराने का एक अवसर और देगी सरकार

**भोपाल।** मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जो आवासीय और व्यावसायिक निर्माण भवन अनुज्ञा में प्राप्त निर्धारित सीमा से अधिक हुए हैं, उन्हें वैध करवाने का एक अवसर और सरकार देगी। अभी 31 अगस्त तक इसकी अनुमति दी गई थी। इस अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने विभागीय मंत्रों के अनुमोदन के लिए भेजा है। यह व्यवस्था निकायों की आय में वृद्धि के लिए मददगार सिद्ध हुई है। मध्य प्रदेश नगर पालिका (अनुज्ञा के बिना भवनों के संनिर्माण के अपराधों का प्रशमन, शुल्क एवं शर्त) नियम 2016 में अनुज्ञा से अधिक दस प्रतिशत तक निर्माण को वैध किए जाने का प्रविधान है। विधानसभा चुनाव के समय नियम में संशोधन करके सीमा 30 प्रतिशत



तक निर्धारित कर दी गई थी। इससे इंदौर, भोपाल सहित अन्य नगरीय निकायों को करोड़ों रुपये प्राप्त हुए। इस वर्ष अनुमति से 30 प्रतिशत तक अधिक आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को वैध कराने की सुविधा नियम में संशोधन कर

31 अगस्त 2024 तक दी गई थी। **बाजार मूल्य की दर का 12 प्रतिशत बराबर लगेगा शुल्क**— विभागीय अधिकारियों का कहना है कि भवन के 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक अनधिकृत निर्माण ही वैध किया जा सकेगा। इसके लिए

संबंधित क्षेत्र की कलेक्टर गाइड लाइन द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की दर का 12 प्रतिशत के बराबर शुल्क लेकर निर्माण वैध किया जा सकेगा। भवन के व्यावसायिक उपयोग के मामले में यह शुल्क 18 प्रतिशत लगेगा।

**प्रत्येक 15 दिन में हो रही समीक्षा**— नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त भरत यादव प्रत्येक 15 दिवस में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी निकायों के अधिकारियों से चर्चा करके जानकारी लेते हैं। उनका कहना है कि जल कर, संपत्ति कर सहित अन्य करों के माध्यम से निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

ग्वालियर में 6 अक्टूबर को होने वाले भारत-बांग्लादेश टी-20 मैच का विरोध करने सड़कों पर उतरेगी हिंदू महासभा

## मैच के टिकट खरीदने वालों को हिंदू महासभा ने कहा राष्ट्रद्रोही

**भोपाल।** ग्वालियर जिले में 6 अक्टूबर को होने वाले टी-20 मैच को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने लश्कर बंद का आह्वान किया है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने दो दिन में मैच के सभी टिकट बिकने पर टिकट खरीदने वालों को राष्ट्रद्रोही करार दिया है। हिंदू महासभा ने एलान किया है कि ग्वालियर में छह अक्टूबर को होने वाले भारत बांग्लादेश टी-20 मैच का हम खुलकर विरोध करेंगे, हिंदू महासभा सड़कों पर उतरेगी। बता दें कि ग्वालियर में भारत-बांग्लादेश के बीच टी-20 मैच का आयोजन के एलान के साथ ही हिंदू महासभा ने अपना विरोध जता दिया था। अखिल भारतीय



हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र लिखकर मैच रद्द करने की मांग की थी। लेकिन बीसीसीआई और एमपीसीए द्वारा मैच द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसे लेकर

हिंदू संगठन आक्रोशित हैं। इसके साथ ही टी-20 मैच पर असमंजस के बादल छा गए हैं। हालांकि, बीसीसीआई और एमपीसीए के मुताबिक बांग्लादेश और भारत के खिलाड़ियों की

सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। लेकिन हिंदू संगठनों के आक्रोश के चलते शासन-प्रशासन भी परेशान नजर आ रहा है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने कहा है कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। हिंदुओं की मां-बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश की टीम यहां पर आएगी तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने लोगों से भी मांग की है कि इस मैच को स्टेडियम में देखने न जाएं और इसका विरोध करने के लिए हिंदू महासभा का समर्थन करें। क्योंकि यह हमारे हिंदू भाइयों और मां-बेटियों की सुरक्षा का सवाल है।

देशभर के 34 आयुर्वेद कॉलेजों की मान्यता पर रोक, मप्र का भी एक शामिल

**भोपाल।** केंद्रीय आयुष मंत्रालय की सहमति पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग एनसीआईएसएम नई दिल्ली ने देशभर के 34 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर रोक लगा दी है। इसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात के एक-एक आयुर्वेद कॉलेज, बिहार व पंजाब के दो-दो, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड के तीन-तीन कॉलेज, उत्तर प्रदेश के 17 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश पांडेय ने बताया कि इन 34 कॉलेजों में 31 निजी कॉलेज हैं और तीन शासकीय आयुर्वेद कॉलेज बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान (अजमेर) के हैं। देशभर में 474 मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेज हैं, जहां पर सेंट्रल व स्टेट कोटे की सत्र 2024-25 की नीट यूजी काउंसलिंग जारी है।

फुटकर विक्रेता 5 मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे दालों का स्टॉक

**भोपाल।** मध्य प्रदेश में गेहूं के बाद अब दाल (तुअर और चना) के भंडार की सीमा भी सरकार ने निर्धारित कर दी है। कोई भी फुटकर विक्रेता अब एक समय में पांच मीट्रिक टन से अधिक दाल का भंडारण करके नहीं रख सकेगा। थोक विक्रेताओं के लिए प्रत्येक दाल की यह सीमा 200 मीट्रिक टन से अधिक नहीं होगी। भारत सरकार के निर्देश पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता के लिए प्रत्येक दाल के लिए प्रत्येक आउटलेट पर पांच मीट्रिक टन और प्रत्येक डिपो में 200 मीट्रिक टन दाल के भंडारण की सीमा रहेगी। मिलर तीन माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत तक भंडार रख सकते हैं। भंडारण का लेखा-जोखा प्रत्येक दुकानदार को रखना होगा। जांच के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और अधिक भंडार पाए जाने पर उसे राजसात भी किया जा सकेगा।

65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म करने वाला युवक गिरफ्तार

**भोपाल।** शहर के कोलार थाना इलाके में एक निर्माणाधीन मकान में 63 वर्षीय वृद्धा के साथ दुष्कर्म कर फरार हुए युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 22 वर्षीय दीपक जाटव इलाके के कान्हाकुंज फेस 2, बंजारी का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी तलाश में 105 सीसीटीवी खंगाले और आखिरकार उसे स्वर्ण जयंती पार्क से गिरफ्तार कर लिया। उसने बुजुर्ग महिला को पुराना सामान देने के बहाने बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था। कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया कि वृद्धा सोमवार दोपहर कोलार के बांसखेड़ी में निमाणाधीन मकान के सामने गते बीन रही थी। उसी समय एक युवक ने उसे पहली मंजिल पर गते बीनकर ले जाने के बहाने बुलाया और मारपीट कर दुष्कर्म करने के बाद भाग गया था। कोलार थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी घटनास्थल के पास का निकला। उसकी तलाश के लिए तीन टीमें लगा रखी थी और आसपास के करीब 105 सीसीटीवी खंगाले और 50 से ज्यादा से पूछताछ की गई। वृद्धा ने आरोपी का हुलिया बताया था कि उसका आगे का दांत गायब है और दांतों में काफी गैप है। उसकी उम्र 27 से 30 वर्ष के करीब लग रही थी। वह सफेद रंग की शर्ट और काला पैंट पहने हुए था। वृद्धा के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी फरार था। थाना प्रभारी ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी खंगालने के लिए टीम को लगाया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने नशेड़ियों और पुराने बंदमोशों से भी जानकारी जुटाई। टीआई ने उनको इनाम देने की बात कही थी। रात में एक मुखबिर से सूचना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

सरकारी स्कूलों में राज्य स्तर से तैयार कराए जाएंगे अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न-पत्र

**भोपाल।** स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय व अनुदान प्राप्त शालाओं और डाइस कोड प्राप्त मद्रस्सों में कक्षा 5वीं और 8वीं में अध्ययनरत बच्चों के लिए एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों एवं पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा कराने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही परीक्षा परिणाम के लिए अधिभार अंक निर्धारित किए गए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक अर्द्धवार्षिक परीक्षा के लिए अधिभार अंक 20, वार्षिक परीक्षा लिखित अधिभार अंक 60 और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य के लिए अधिभार अंक 20 निर्धारित किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि समस्त शालाओं में अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा द्वारा निर्धारित ब्लू प्रिंट के आधार पर तैयार कराए गए प्रश्न-पत्रों और निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कराया जाएगा।



## संपादकीय

# मिलावट ही ‘सत्य’ है

आज खाने-पीने की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें गारंटी के साथ कहा जा सके कि इसमें मिलावट नहीं है। मिलावटखोरी का यह धंधा बरसों से पूरे देश में चल रहा है। इसके खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन मिलावट का धंधा रुकने का नाम नहीं लेता। कई राज्य अपने स्तर पर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन सबूतों के अभाव में मिलावटखोर साफ बच जाते हैं। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे दैनिक उपयोग में आने वाली खाद्य वस्तुओं पर निगरानी रखें तथा रोज दंडात्मक कार्रवाई करें। भारत में मिलावट और भ्रष्टाचार कोई नई प्रवृत्तियां नहीं हैं। खाद्य पदार्थ ही नहीं, हमारी हवा और पानी भी प्रदूषित हैं। खाने की चीजों में इनसान की उंगली, छिपकली, सांप के टुकड़े पाए जाने की असंख्य घटनाएं सामने आती रही हैं। कानून तो है, लेकिन खाद्य निरीक्षकों की निगरानी और व्यवस्था गायब और लचर है। उनके अपने हफ्ते या महीना बंधे हैं। दूध में पानी या सोडा मिलाया जाता है, खोया भी मिलावटी और रासायनिक है, देशी घी के नाम पर हम बाबाओं के दावों का अनुसरण करते हैं, लिहाजा भ्रम में जीते हैं कि हम विशुद्ध देशी घी खा रहे हैं। अब कुछ भी शुद्ध मिलना असंभव है, क्योंकि यह मोटे मुनाफे और मिलावट का कलियुग है। आत्मा से हम बेईमान और भ्रष्ट हैं। मुनाफे और मिलावट के लिए कोई भी ठेकेदार भगवान तक को ठग सकता है। आस्था और श्रद्धा को खंडित और अपमानित कर सकते हैं। बेशक मंत्रोच्चारण के जरिए तिरुपति मंदिर का शुद्धिकरण कर लिया गया हो, यह कर्मकांड का आत्मसंतोष हो सकता है, लेकिन करोड़ों भक्तों ने प्रसादमलङ्क का जो ग्रहण किया है, प्रसाद को अन्य भक्तों में भी बांटा है, उनका शुद्धिकरण कैसे संभव है? तिरुपति मंदिर में औसतन 3.5 लाख लड्डू रोजाना भक्तों के हाथों में जाते हैं। प्रसाद के इन लड्डूओं से तिरुपति मंदिर को 500-600 करोड़ रुपए की सालाना कमाई होती है। प्रसाद, मंदिर और कमाई बिल्कुल विरोधाभासी हैं। देश में हिंदू या गैर-हिंदुओं के हजारों मंदिर ऐसी ही दुकानदारी चला रहे हैं। दुकान खोलोगे, तो मिलावटी वस्तुएं भी आएंगी और उन्हें विक्रता का धर्म निभाना पड़ेगा। अब तिरुपति प्रकरण के बाद मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन के भगवान श्रीकृष्ण के मंदिरों में भी जांच का मुद्दा उठाया गया है। वाराणसी के काशी-विश्वनाथ मंदिर में बटने वाले प्रसाद की भी जांच की जाएगी। किसी मंदिर के बाहर नोटिस चिपकाया गया है कि भक्तगण अपने घरों से प्रसाद बनाकर लाएं और मंदिर में भगवान को भोग लगाएं। अथवा ड्राई फ्रूट्स प्रभु के चरणों में चढ़ाए जा सकते हैं। दरअसल बुनियादी मुद्दा और संकट मिलावट और बदनीयत का है।आखिर भक्तगण विशुद्ध दूध और घी कहां से लाएंगे? लिहाजा घर में बना प्रसाद भी अशुद्ध और मिलावटी हो सकता है। यही नहीं, स्कूलों में बच्चों को जो दोपहर का खाना दिया जाता है, वह भी मिलावटी, प्रदूषित होता रहा है, क्योंकि बच्चे वह खाना खाकर बीमार पड़ते रहे हैं। मौतें भी हुई हैं। उस खाने में भी छिपकली और सांप पाए जाते रहे हैं। यह कैसी व्यवस्था है? देश में पूजा-स्थलों और मंदिरों में लोगों की गहरी आस्था और विश्वास होता है। मंदिर के जरिए आम भक्त भगवान से साक्षात्कार महसूस करना चाहता है। अब आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के जरिए यह मुद्दा बेपर्दा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को खलनायक करार दिया जा रहा है। बेशक राज्य सरकार ने सभी पुराने ठेके, सप्लाइ आदि को रद्द कर दिया है। विशेष जांच दल भी गठित कर दिया गया है, लेकिन अतंतः यह सियासी खुन्नस का मामला भी साबित हो सकता है। इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो चुकी है, जबकि बुनियादी मुद्दा मंदिरों में जाने वाले भक्त की आस्था और मिलावट के जरिए उसकी आत्मा को अपवित्र करने की हसरतों का है। अभी लड्डू प्रसादमकी वैज्ञानिक जांच सामने आनी है। देश की सबसे बड़ी और सार्थक प्रयोगशाला हैदराबाद में है, जबकि पूरी चिल्ल-पों की आधार गुजरात की लैब की रपट है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बहुराष्ट्रीय अध्ययन के संदर्भ में भारत के 17 शहरों से भी कुछ नमूने लिए। निष्कर्ष यह रहा कि 14 फीसदी नमूनों में उच्च स्तर की धातु मिलाई गई थी। बेशक दूध के क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन ने विकास की बुलंदियां छुई हैं, लेकिन आधा से ज्यादा क्षेत्र अब भी असंगठित है। इसमें घी बनाने वाली इकाइयां भी हैं। संसद को यह बताया गया था कि 3 में से 2 भारतीय जो दूध का उपयोग करते हैं, उसमें डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, यूरिया अथवा पेंट आदि मिले होते हैं। इतने व्यापक स्तर पर मिलावट को किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है। लड्डू प्रकरण के बाद जो भी जांच के दौर निभाए जाएं, लेकिन यही हमारी नियति रहेगी कि मिलावट ही अंतिम सत्य है। आज खाने-पीने की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें गारंटी के साथ कहा जा सके कि इसमें मिलावट नहीं है। मिलावटखोरी का यह धंधा बरसों से पूरे देश में चल रहा है। इसके खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन मिलावट का धंधा रुकने का नाम नहीं लेता। कई राज्य अपने स्तर पर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन सबूतों के अभाव में मिलावटखोर साफ बच जाते हैं। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे दैनिक उपयोग में आने वाली खाद्य वस्तुओं पर निगरानी रखें तथा रोज दंडात्मक कार्रवाई करें।

# हिंदुत्व को कट्टरवादी विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं वामपंथी इतिहासकार

भारत की हजारों वर्षों की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं इस बात का साक्षात्कार करती हैं कि हिंदुत्व का विकास शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और विविध धार्मिक मान्यताओं के सम्मान पर आधारित रहा है। वामपंथी इतिहासकार हिंदुत्व को अक्सर एक संकीर्ण और कट्टरवादी विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं। उनकी यह धारणा है कि हिंदुत्व भारतीय समाज में साम्प्रदायिकता और विभाजन को बढ़ावा देता है। वे इसे एक ऐसी विचारधारा के रूप में देखते हैं जो गैर-हिंदू समुदायों के प्रति असहिष्णु है और भारत की बहुलवादी पहचान के लिए खतरा है। हिंदुत्व जो प्रत्येक हिंदू की अंतरआत्मा में निहित है वह केवल एक धार्मिक विचारधारा नहीं है, बल्कि एक जीवनशैली, एक दर्शन और एक सामाजिक व्यवहार है जो हजारों वर्षों से हिंदू समाज का मार्गदर्शन करता आया है। हिंदुत्व केवल एक धर्म का नहीं, बल्कि एक जीवनशैली, एक विचारधारा और एक गहन सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। यह हिंदू समाज की आत्मा में निहित विचारधारा है, जो उसे उसकी परंपराओं, रीति-रिवाजों और मान्यताओं से जोड़ती है। हिंदुत्व को अक्सर एक संकीर्ण परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, जहां इसे कट्टरवाद या अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परंतु सच्चाई इससे कहीं अधिक व्यापक और गहन है। हिंदुत्व का अर्थ केवल धर्म या धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण हिंदू संस्कृति, परंपराओं, सामाजिक व्यवस्थाओं और जीवन के सभी पहलुओं को समाहित करता है। सावरकर ने इसे व्यापक रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि हिंदुत्व का मतलब हिंदू होना नहीं है, बल्कि वह भावना है जो हिंदू समाज को एकजुट करती है। यह दर्शन न केवल धार्मिक मूल्यों पर आधारित है, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी गहरे रूप से जड़ित है। वामपंथी इतिहासकारों ने अक्सर हिंदुत्व को धर्म के संकीर्ण दृष्टिकोण से देखा है, जो कि हिंदुत्व की वास्तविक व्यापकता को समझने में असमर्थता दर्शाता है। हिंदुत्व किसी एक धर्म या पंथ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की समग्रता का प्रतीक है, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों में समरसता और संतुलन की भावना को महत्व दिया गया है। हिंदुत्व की अवधारणा सदियों पुरानी है। यह केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक धरोहर, रीति-रिवाजों, परंपराओं और दर्शन का मूल स्रोत है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म ने ह्रस्वधर्म समभावद्ध और ह्रवसुधैव कुटुंबकम्ह जैसे विचारों को अपने केंद्र में रखा है। हिंदुत्व इसी उदारता और समावेशी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के सांस्कृतिक एकीकरण के संदर्भ में यह विचारधारा महत्वपूर्ण है, जहां विभिन्न भाषाओं, जातियों और धर्मों के बावजूद एक गहरी सांस्कृतिक एकता है। वामपंथी इतिहासकारों द्वारा यह कहा गया है कि हिंदुत्व एक आधुनिक औपनिवेशिक निर्माण है और इसका इतिहास में कोई ठोस आधार नहीं है। यह धारणा हिंदुत्व के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार की गलत समझ पर आधारित है। प्राचीन ग्रंथों और वैदिक साहित्य में जो विचारधाराएं प्रस्तुत की गई हैं, वे स्पष्ट रूप से हिंदुत्व के विचार को समर्थन देती हैं। यज्ञ, तप, ध्यान, और दान जैसे धार्मिक कार्यों के माध्यम से एक व्यक्ति को व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति के मार्ग



पर प्रेरित किया गया। ये कार्य केवल धर्म के रूप में नहीं, बल्कि एक समग्र जीवनशैली के रूप में देखे गए, जो हिंदुत्व का मूल सिद्धांत है। हिंदुत्व की जड़ें वैदिक काल से लेकर आज तक की भारतीय सभ्यता में फैली हुई हैं। वैदिक काल में आर्य समाज के मूल्यों और आध्यात्मिक विचारधारा के माध्यम से हिंदुत्व का विकास हुआ। इसके बाद, महाकाव्यों, जैसे कि रामायण और महाभारत, ने हिंदू समाज को धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक दिशा दी। भक्ति आंदोलन और वेदांत दर्शन ने हिंदुत्व की आध्यात्मिक गहराई को बढ़ावा दिया, जबकि विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलनों ने इसे समयानुसार परिकृत किया। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि वामपंथी इतिहासकार अक्सर भारतीय इतिहास के इस महान विकास को विकृत करने का प्रयास करते हैं, इसे सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हुए। जबकि सच्चाई यह है कि हिंदुत्व के मूल में सार्वभौमिकता, सहिष्णुता और विविधता के प्रति सम्मान है। भारत की हजारों वर्षों की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं इस बात का साक्षात्कार करती हैं कि हिंदुत्व का विकास शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और विविध धार्मिक मान्यताओं के सम्मान पर आधारित रहा है। वामपंथी इतिहासकार हिंदुत्व को अक्सर एक संकीर्ण और कट्टरवादी विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं। उनकी यह धारणा है कि हिंदुत्व भारतीय समाज में साम्प्रदायिकता और विभाजन को बढ़ावा देता है। वे इसे एक ऐसी विचारधारा के रूप में देखते हैं जो गैर-हिंदू समुदायों के प्रति असहिष्णु है और भारत की बहुलवादी पहचान के लिए खतरा है। लेकिन यह दृष्टिकोण हिंदुत्व के वास्तविक स्वरूप को गलत ढंग से समझने का परिणाम है। वास्तव में, हिंदुत्व का उद्देश्य संपूर्ण भारतीय समाज को एकजुट करना है। यह सभी धर्मों और मान्यताओं के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का प्रचार करता है। हिंदुत्व के अनुसार, भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और यह विविधता सह-अस्तित्व की भावना के आधार पर संरक्षित और संवर्धित होनी चाहिए। वामपंथी इतिहासकारों का यह तर्क कि हिंदुत्व विभाजनकारी है, वस्तुतः हिंदुत्व की वास्तविकता से दूर है। उनका मानना ​​है कि यह विचारधारा केवल हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करती है और अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु है। लेकिन यह दृष्टिकोण

ऐतिहासिक तथ्यों और हिंदुत्व की वास्तविक परिभाषा से परे है। हिंदुत्व की जड़ें उस समावेशी परंपरा में हैं, जो विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को आत्मसात करने की क्षमता रखती है। भारत में बौद्ध, जैन और सिख पंथ के साथ-साथ इस्लाम और ईसाई पंथ ने भी अपनी पहचान बनाई, लेकिन यह सब हिंदुत्व की व्यापक छाया में फलते-फूलते रहे हैं। वामपंथी विमर्श अक्सर यह तर्क देता है कि हिंदुत्व भारतीय समाज के भीतर सामाजिक विभाजन और जातिवाद को बढ़ावा देता है। हालांकि, वास्तविकता यह है कि हिंदुत्व का आदर्श जाति और वर्ग के पार जाकर एक समावेशी समाज की स्थापना करना है। इसके प्रमाण हमें स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी मिलते हैं, जब हिंदू और मुसलमान दोनों ही एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़े। हिंदुत्व ने कभी भी विभाजन की राजनीति को प्रोत्साहित नहीं किया; बल्कि इसका उद्देश्य हमेशा से एक अखंड और समावेशी समाज की स्थापना रहा है। हिंदुत्व केवल धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के राष्ट्रीय चरित्र का एक अभिन्न अंग है। गांधी से लेकर विवेकानंद तक, सभी ने भारतीय संस्कृति और हिंदू दर्शन को राष्ट्रीय पुनर्जागरण के संदर्भ में देखा है। हिंदुत्व ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी प्रेरित किया और भारतीय समाज को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वामपंथी इतिहासकार इस तथ्य को अनदेखा करते हैं कि हिंदुत्व ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी और इसे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में प्रेरित किया। वे हिंदुत्व के इस पक्ष को दरकिनार करते हैं और इसे केवल सांप्रदायिकता के चश्मे से देखते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि हिंदुत्व का उद्देश्य न केवल धार्मिक जागरूकता बढ़ाना है, बल्कि भारतीय समाज के सभी वर्गों को एकता के सूत्र में पिरोना है। हिंदुत्व की एक विशेषता यह है कि यह सहिष्णुता और विविधता का सम्मान करता है। हिंदुत्व में एक ही परब्रह्म की अलग-अलग स्वरूपों में उपासना की जाती है, और यह बहुलवाद भारतीय समाज की आत्मा में गहराई से रचा-बसा हुआ है। हिंदुत्व का दर्शन यह सिखाता है कि सभी पंथ और विचारधाराएं एक ही परम सत्य की ओर ले जाती हैं। यह सहिष्णुता और समावेशिता हिंदुत्व के मूल में है, जो वामपंथी इतिहासकारों के कट्टरता के आरोपों को खारिज करता है। वास्तव में,

हिंदू समाज ने ऐतिहासिक रूप से यह साबित किया है कि वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों को स्वीकार करता है और उन्हें समाहित करने की क्षमता रखता है। भारत में पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन, सिख और मुस्लिम समुदायों का समृद्ध इतिहास इस बात का प्रमाण है कि हिंदुत्व सह-अस्तित्व और सहयोग का प्रतीक है। वामपंथी आलोचनाओं के विपरीत, हिंदुत्व का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पहचानों एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में रहें। आधुनिक भारत में हिंदुत्व ने न केवल सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान दिया है, बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी सुधार किए हैं। हिंदुत्व आधारित संगठनों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकार, दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान, और पारिवारिक मूल्यों की पुनर्स्थापना में भी हिंदुत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वामपंथी इतिहासकारों द्वारा हिंदुत्व को केवल सांप्रदायिकता और राजनीति से जोड़ना गलत है। हिंदुत्व ने भारतीय समाज के समग्र विकास में योगदान दिया है और यह केवल एक राजनीतिक विचारधारा नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन भी है। भारतीय संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप, हिंदुत्व भारतीय समाज में समता, स्वतंत्रता, और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है। अंततः, हिंदुत्व प्रत्येक हिंदू की आत्मा में गहराई से निहित है, अविभाज्य संबंध है। यह केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। वामपंथी इतिहासकारों ने इसे जिस प्रकार से विकृत किया है, वह न केवल गलत है, बल्कि भारतीय सभ्यता के मूल्यों और आदर्शों के खिलाफ भी है। हिंदुत्व न केवल हिंदुओं के लिए, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो सहिष्णुता, समरसता, और विविधता को महत्व देता है। आधुनिक भारत के संदर्भ में, हिंदुत्व एक सकारात्मक विचारधारा के रूप में उभर कर सामने आया है, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और संवर्धित करता है। इसे केवल राजनीति या सांप्रदायिकता के चश्मे से देखने की बजाय, इसे भारत की आत्मा और उसकी सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

# रैगिंग से छात्रों को मुक्ति कब?

इस तरह के दस्तावेज में किसी भी लिखित कदाचार का उल्लेख किया जाएगा और कॉलेज, आवेदक पर नजर रख सकता है। यह दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ नथी होना चाहिए। हॉस्टल वार्डनों, छात्रों, अभिभावकों आदि के प्रतिनिधियों के साथ रैगिंग रोकने के उपायों और कदमों पर चर्चा करें। इस समय रैगिंग से जुड़ी विकराल घटनाओं के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन बुनियादी तौर पर निक्कमे प्रशासनिक प्रबंधन के कारण जिम्मेवार कहे जा सकते हैं, जो छात्रों को नैतिक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कुछ रोज पहले हिमाचल प्रदेश की एक निजी यूनिवर्सिटी में नए छात्रों की रैगिंग का मामला सामने आया। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि रैगिंग से पीड़ित छात्र ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसे कमरे में बुलाया और फिर शराब पीने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। बाद में आरोपियों ने कमरा बंद कर सुबह तक उसके साथ मारपीट की। मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां की सरकार ने शिक्षा सचिव को इसकी

जांच के भी आदेश दिए हैं और जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। रैगिंग की समस्या उच्च शिक्षा जगत से जुड़ी अत्यंत संवेदनशील, सामाजिक समस्या है, जिससे उच्च शिक्षा जगत को पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिल पाई है। इस समय देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद देश के अनेक उच्च शिक्षा संस्थान इससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। आइए, छात्रों की शिक्षा संस्थानों में रैगिंग को लेकर कुछ खस बातों को जानें। एक शिक्षण संस्थान के किसी अन्य छात्र के खिलाफ एक छात्र द्वारा किए गए किसी भी शारीरिक, मौखिक या मानसिक दुर्व्यवहार को रैगिंग कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौनसा छात्र इसे करता है या किस छात्र के साथ यह दुर्व्यवहार किया जाता है। रैगिंग एक ऐसा शब्द है जो हर साल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्लास शुरू होते ही सुनाई देने लगता है। दुनियाभर में हर साल लाखों स्टूडेंट्स को इसका सामना करना पड़ता है। रैगिंग को दुनिया में अलग-अलग नामों से पहचाना जाता है। इसको

हेजिंग, फेंगिंग, बुलिंग, प्लेजिंग और हॉर्स प्लेइंग के नामों से भी जाना जाता है। रैगिंग कई कारणों से हो सकती है, जैसे आपकी त्वचा, नस्ल, धर्म, जाति, प्रजातीयता, जेंडर, यौनिक रुझान, रूप-रंग, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय मूल, आपकी बोली, जगह, स्थान, गृह स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण इसमें शामिल हैं। रैगिंग कई अलग-अलग रूप ले सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र किसी अन्य छात्र को उसके काम करने के लिए धौंस दिखाता है या किसी छात्र को कॉलेज समारोह जैसी परिसर की गतिविधियों से बाहर रखा जाता है, तो उसे रैगिंग माना जाता है। मानसिक चोट, शारीरिक दुर्व्यवहार, भेदभाव, शैक्षणिक गतिविधि में व्यवधान आदि सहित छात्रों के खिलाफ रैगिंग के विभिन्न रूपों को कानून दंडित करता है। जहां तक रैगिंग के शुरू होने से जुड़े इतिहास का संबंध है, तो माना जाता है कि 7 से 8वीं शताब्दी में ग्रीस के खेल समुदायों में नए खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स स्पिरिट जगाने के उद्देश्य से रैगिंग की शुरुआत हुई। इसमें

जूनियर खिलाड़ियों को चिढ़ाया और अपमानित किया जाता था। यह कार्य खेल के साथ-साथ बढ़ता गया और रैगिंग में बदलता गया। इसके बाद सेना में भी इसको अपनाया गया। खेल और सेना के बाद रैगिंग से शिक्षण संस्थान भी नहीं बचे और छात्रों ने इसको अपनाकर भयावह रूप दे दिया। धीरे-धीरे कॉलेजों में शैक्षणिक क्षेत्र में जगह बनाने के बाद रैगिंग हिंसक हो गई और इसके लिए बकायदा ग्रुप बन गए। 18वीं शताब्दी के दौरान विश्वविद्यालयों में छात्र संगठन बनने लगे जिनमें विशेष रूप से यूरोपीय देश शामिल थे। इन संगठनों के नाम अल्फा, बीटा, कप्पा, एप्सिलोन, डेल्टा आदि जैसे ग्रीक अक्षरों के नाम पर रखे जाने लगे। भारत में रैगिंग की शुरुआत आजादी से पहले ही हो गई थी। इसकी शुरुआत अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा से हुई। हालांकि भारत में रैगिंग का अलग तरीका था जिसमें सीनियर और जूनियर के बीच दोस्ती बढ़ाने के लिए हल्की-फुल्की रैगिंग की जाती थी। इसमें शालीनता का परिचय दिया जाता था। लेकिन 90 के दशक में भारत में रैगिंग

ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में रैगिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही यूजीसी ने भी रैगिंग के खिलाफ सख्त नियम बनाए हैं। रैगिंग पर कुछ शिक्षण संस्थानों के अपने नियम हैं। उदाहरण के लिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के पास रैगिंग पर दिशा-निर्देशों की अपनी एक नियमावली है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में रैगिंग को प्रतिबंधित करने व रोकने के लिहाज से विभिन्न राज्यों ने कानून पारित किए हैं, जो केवल उन संबंधित राज्यों में ही लागू होते हैं। क्या सभी राज्यों में सरकारों ने ऐसे कानून बनाए हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने 16 महीनों में रैगिंग की 90 फीसदी शिकायतों के निपटारे का दावा किया है। यूजीसी के मुताबिक, एक जनवरी 2023 से 28 अप्रैल 2024 तक अलग-अलग यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा संस्थानों से छात्रों की 1240 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 1113 (89.76 फीसदी) का निपटारा किया गया है। शिकायतों का निपटारा सिर्फ काफी नहीं होगा, कसूरवारों को सख्त सजा ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। देश के सभी राज्यों में रैगिंग को लाकर जीरो टोलरेंस की नीति पर काम करना चाहिए। सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को, छात्रों के प्रवेश

के समय रैगिंग रोकने के उपाय करने चाहिए। इनमें से कुछ हैं = एक सार्वजनिक घोषणा (किसी भी प्रारूप में- फ्रंट, ऑडियो, विड्युअल आदि) करें कि कॉलेज में रैगिंग पूरी तरह से निषिद्ध है, और जो कोई भी छात्रों की रैगिंग करता पाया जाएगा, उसे कानून के तहत दंडित किया जाएगा। प्रवेश की विवरणिका में रैगिंग के बारे में जानकारी दें। उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए यूजीसी नियमनों 2009 (यूजीसी गाइडलाइंस) को सुदृष्टित किया जाना चाहिए। साथ ही सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, जैसे कि प्रमुख, हॉस्टल वार्डन, आदि की जानकारी, साथ ही एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन का नंबर भी छपना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ एक शपथ पत्र प्रदान करें। छात्रों और अभिभावकों के लिए ये हलफनामे में लिखा होना चाहिए कि छात्र और माता-पिता ने यूजीसी के दिशानिर्देशों को पढ़ा और समझा है, वे जानते हैं कि रैगिंग निषिद्ध है और आवेदक किसी भी तरह की रैगिंग में शामिल नहीं होगा, और ऐसे किसी भी व्यवहार में लिप्त पाए जाने पर वह सजा के लिए उत्तरदायी होगा या होगी। छात्रावास के लिए आवेदन करने पर आवेदक को अतिरिक्त शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर करने होंगे।









## कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सिग्रामपुर में प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक न्य कार्यक्रम हेतु स्थलों का लिया जायजा

**धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ ।** दमोह, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी, सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा और डीएफओ एम.एस. उईके के साथ 05 अक्टूबर को सिग्रामपुर में प्रस्तावित कैबिनेट और लाइली बहना और स्व-सहायता समूह सम्मेलन के लिए स्थलों का जायजा लिया। कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु उन्होंने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर जायजा लिया। इस संबंध में, उन्होंने अधिकारियों से चर्चा भी की। इस अवसर पर एडीशनल एसपी संदीप मिश्रा, एसडीएम, अविनाश रावत, एसडीओ पुलिस , तहसीलदार डॉ. विवेक व्यास सहित अन्य जिला अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा 05 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक सिग्रामपुर में प्रस्तावित है, इसके अलावा एक आमसभा भी संभावित है। इस दृष्टि से सारे इंतेजामात को देखने के लिए एसपी सोमवंशी, सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा, डी.एफ.ओ. महेंद्र उईके, एस.डी.एम., पुलिस प्रशासन और बाकी सभी अधिकारीगण यहां पर आकर सभी स्थानों का जायजा लिया, ट्रॉफिक की व्यवस्था,



पार्किंग की व्यवस्था, टेंट कहां लगेंगे, कैसे पूरे इंतेजामात होंगे, उसके बारे में पूरा ओवरव्यू लिया है। उन्होंने कहा दो-तीन दिन पहले मंत्री जी के साथ आए थे, आज कुछ और वैकल्पिक जगहों को देखा है, ताकि शीघ्र डिस्मिशन लिया जा सके कि कहां पर कैसी व्यवस्थाएं करनी हैं, इसी सिलसिले में सभी जगह का भ्रमण किया है। कलेक्टर ने कहा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री , मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, मुख्य सचिव, डीजीपी और संबंधित विभागों के मुख्य सचिव सभी सम्मिलित होंगे, इसके अलावा एक आमसभा भी प्रस्तावित है, जिसमें लाइली बहना सम्मेलन और स्व-सहायता समूह सम्मेलन की संभावना है, यहां एक आम सभा का कार्यक्रम होगा, इस

तरह से दो बड़े कार्यक्रम यहां पर आयोजित होना प्रस्तावित है पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने कहा 05 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग यहां पर होनी है, उसके लिए पूरा प्रशासन यहां पर मौजूद है। कहां-कहां पर प्रोग्राम करने हैं, हेलीपैड की क्या व्यवस्था होगी, यदि आमसभा होती है तो वह कहां पर होगी, उसमें आने-जाने के रास्ते और पार्किंग व्यवस्था पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा पूरे प्रोग्राम को देखते हुए कितना फोर्स का डेप्लॉयमेंट करना है और मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी के लिए क्या-क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, उसके विषय में चर्चा हुई है। अगले दो से तीन दिनों में इस पूरे प्लान को फाइनलाइज कर लेंगे और यह प्रोग्राम अच्छे से करेंगे।

## पूर्वजों की स्मृति में किया पौधारोपण

**भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ** शाजापुर, हिंदू धर्म के पावन पर्व श्राद्ध पक्ष में गुरु श्रीगोरखनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन योगी नाथ संप्रदाय शाजापुर के समाजजनों द्वारा समाधि भूमि पर बुधवार को सामुहिक समाधि पूजन कर पूर्वजों की स्मृति में पौधारोपण किया गया। फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष चंचलनाथ योगी ने बताया कि श्राद्ध पक्ष पूर्वजों की स्मृति एवं उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर है। इसी के चलते समाधि भूमि पर सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से एक टीन शेड, बैठने हेतु कुर्सियां, बाड़ंडी वाल आदि उपलब्ध करवाने का विचार किया गया। इस



दौरान समस्त नाथ समाजजनों द्वारा अपने-अपने पितरों की स्मृति में एक पौधा भी लगाया गया, जिसे सुरक्षित लोहे की जालियों के माध्यम से समाधि भूमि पर सुरक्षित किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत गिरवर सरपंच सहित समाज के

वरिष्ठ अध्यक्ष अशोक नाथ, मंगल नाथ, जगदीश नाथ, जीवन नाथ, सुनील नाथ, भेरु नाथ, मुकेश नाथ, दीपक नाथ, विशाल नाथ, विकास नाथ, विककी नाथ, लकी नाथ, बद्री नाथ योगी सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे।

## मक्सी में हुई घटना को लेकर पुलिस बल मौके पर मौजूद, स्थिति नियंत्रण में

**भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ ।** शाजापुर, मक्सी में विगत 23 सितंबर 2024 को रात्रि करीबन 09.30 बजे एक ही पक्ष के समीर पिता सईद खान एवं अनीस पिता मजीद खान, जावेद पिता मजीद खान, इमरान पिता मजीद खान, आकिब उर्फ अक्का पिता आबिद खान के मध्य आपसी विवाद में थाना मक्सी में धारा 333, 119(1), 115(2), 296, 351(2), 3(5) बीएनएस अन्तर्गत कायमी की गई। उक्त घटना के पश्चात आरोपी अनीस खाँ को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया जो जेल वारंट बनने से जेल दाखिल किया गया शेष आरोपीगण फरार है।आज 25 सितंबर 2024 को रात्रि 08.00 बजे के लगभग नारपति हनुमान मन्दिर मक्सी के सामने दो पक्षों के मध्य पत्थर बाजी हुई, जिसमें गोली चलने की आम लोगो द्वारा बात की जा रही है। उक्त



विवाद मक्सी में दो दिन पूर्व एक ही पक्ष के दो लोगो के मध्य हुए विवाद से जुड़ा है, जिसकी कायमी भी मक्सी थाने पर हुई थी। उक्त घटना के कारण ही आज की घटना कारित होना आम लोगो द्वारा बताया गया है।उक्त घटना में अमजद खान पिता मजीद खान, इकबाल पिता युनुस खान, अरबाज पिता शकिल, जुनैद पिता शाबिर खान, अरजान पिता आरिफ खान, रिहान पिता इरशाद खान व अरबाज

पिता शाजिद घायल हुए है, जिन्हे उचित ईलाज के लिए जिला अस्पताल शाजापुर रेफर किया गया है। ईलाज के दौरान अमजद खान पिता मजीद खान की मृत्यु हुई है।घटना स्थल पर कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना एवं पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह राजपूत मय पुलिस बल के उपस्थित हैं। अतिरिक्त बल आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हैं और मक्सी नगर में शांति हैं।

## यातायात पुलिस की वसूली सुर्खियों में चेकिंग के नाम पर मांग रहे खर्चा पानी

**उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ ।** सतना, जिले में विगत कुछ वर्ष पूर्व चेकिंग के नाम पर एक फर्जीवाड़ा सामने आया था जिसमें यातायात विभाग के कुछ कर्मचारी निलंबित भी हुए थे। लेकिन इसके बाद भी मातहत कर्मचारी वसूली से वाज नहीं आ रहे हैं। अवैध वसूली का सुरूर इस तरह सिर चढ़कर नाच रहा है की जो भी मिले वही बहुत है मंगलवार को सतना नदी के पास यातायात के वसूली वाजों ने फोर व्हीलर की चेकिंग लगाए हुए थे जिसमे 200 रुपए से अवैध वसूली चालू हुई थी चालान कितने कटे कितने नही कटे थे तो चालान बुक ही बता सकती है लेकिन वसूली वाजों ने अपनी जेब भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे है एक हार्वेस्टर वाले से 200 रुपए अवैध तरीके से लिए वहीं मैजिक गाड़ी वाले से 2000 हजार की मांग थी लेकिन 500 रुपए में मामला रफा



दफा कर दिए और रसीद भी नहीं दिए आखिर कब तक ये यातायात की अवैध वसूली करने वाले आम जनता का खून चूसते रहेंगे क्या इन पर कभी बड़ी कुर्सी वाले, जिले के बड़े अधिकारी, कार्यवाही भी करेंगे या फिर ऐसा तमाशा ही चलता है रहेगा आम जनता का कहना है की वसूली बाज इंसान देखकर चालानी कार्यवाही करते है आखिर इतना दुराभाव क्यों किया जा रहा है

यातायात के ये वसूली बाज सुबह 10 या 11 बजे निकलते है इनका एक ही ध्येय है और चिंता रहती है की आज अपने अपने हिस्से में कितना पैसा आएगा और कितने लोगों का खून चूसना है। आखिर कब इस अवैध वसूली के खिलाफ नेताओ की आवाज सुनाई देगी या फिर ऐसे ही आम जनता को लुटवाने में इन वसूली वाजों को अनदेखा करते रहेंगे। आम जनता इस समय यातायात

के वसूली वाजों से त्रस्त हो चुकी है और इधर उधर से भाग रही है अगर किसी दिन कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, यातायात थाने के वसूली बाज या जिले के अधिकारी? **वसूली का मुख्य मास्टर मांडड है उग्रेश सिंह** उग्रेश सिंह यातायात थाने में विगत कई वर्षों से पदस्थ है। जिनके वसूली की चर्चा कई बार सोसल मीडिया में भी सामने आ चुकी है। सूत्रों की मानें तो सतना नदी के पास चेकिंग के नाम पर लगातार वसूली चल रही है। जिसमें प्रमुख भूमिका उग्रेश सिंह की बताई जा रही है। इतना ही नहीं उग्रेश सिंह के द्वारा पूरे शहर में वसूली किये जाने की जानकारी सामने आ रही है। ऐसे वसूलीवाज कर्मचारियों को यातायात से हटाये जाने की जरूरत है। ऐसे वसूलीवाज कर्मचारी कहीं न कहीं पुलिस अधीक्षक की छवि को

## एक साथ उठी 9 अर्थियों ने दमोह को दहला दिया दमोह जिले में सड़क दुर्घटना रोकने में सहभागी बने आमजन

**धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ** दमोह, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर कल ग्राम समना के समीप कटनी मार्ग पर हुई भीषण दुर्घटना से दुखित होते हुए कहा दमोह के गुप्ता परिवार के 09 लोगों का सड़क दुर्घटना में निधन के समाचार ने पूरे दमोह को झकझोर कर रख दिया है। क्या आप उस घनघोर पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं , जिससे परिवार के सदस्य गुजर रहे होंगे, साधारण परिस्थिति में अपने जीवन का गुजारा करने वाले एक परिवार के लिए ये सचमुच असाधारण दुःख की बेला है। आज किसी ने बेटा, किसी ने पिता , किसी ने भाई, किसी ने बहन , किसी ने मां को खड़े कर देने वाली घटना में एक्सीडेंट के स्पॉट से लेकर पीड़ित परिवार के घर तक दमोह का जन – जन संकट का साथी बनकर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए उमड़ पड़ा । मीडिया के साथी , समाज सेवी संगठन, स्वयं सेवी संस्थाएं, राज्य सरकार, सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, स्थानीय नागरिक



और चिकित्सकों- सभी ने जिला पुलिस और प्रशासन को जो सहयोग दिया , वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। सभी के प्रति हृदय से आभार। कलेक्टर ने कहा लेकिन यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है और उसका जवाब भी चाहती है। क्या इतनी बड़ी घटना हमारे लिए पहला और आखरी सबक नहीं होना चाहिए कि सड़क पर जीवन रक्षा को लेकर अब बहुत सतर्क और सख्त होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि एक्सीडेंट के कारक कुछ गंभीर विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे – नशे

में वाहन चलाना, बिना वैध लाइसेंस/परमिट के वाहन चलाना, अनफिट वाहन से यात्रियों का परिवहन, वाहन की तय क्षमता से अधिक सवारी या सामान भरकर ले जाना, रिंग साइड चलना, बहुत खड़ा करती है और उसका जवाब भी चाहती है। क्या इतनी बड़ी घटना हमारे लिए पहला और आखरी सबक नहीं होना चाहिए कि सड़क पर जीवन रक्षा को लेकर अब बहुत सतर्क और सख्त होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि एक्सीडेंट के कारक कुछ गंभीर विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे – नशे

### आरटीओ कार्यालय में नही होता बिना चढ़ावे के कोई काम दलालों का है बोल बाला

**यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ** अनुपपुर, अनुपपुर आर टी ओ उड़नदस्ता हो या आर टी ओ कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी सभी की एक ही मन ओर मनसा रहती है , की किसी भी तरह अपनी जेब भरी जाए चाहे उसके लिए किसी गरीब का गला भी काटना पड़े तो ये पीछे नहीं हटते हालांकि ये एक कहावत है लेकिन आर टी ओ कार्यालय में जेब जरूर कटती है , आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाए सरकारी शुल्क के उपर लगभग 2000का खर्च लगना



ही है , एक वेयक्ति से शुल्क के अलावा 2000तो दिन भर में 10लाइसेंस भी माने तो 20000 रोज ये ही नही बस परमिट के लिए भी शासकीय शुल्क के अलावा लगभग 10000 उपर की राशि लगती है हर कार्य का यह शासकीय शुल्क के अलावा उपर

के रेट की लिस्ट है। यहाँ इस ऑफिस में दलाल हर समय सक्रिय रहते हैं और सारे दलालों से साहब का कमीशन बंधा हुआ होता है , तभी तो यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस हेतु न ही गाड़ी का ट्रायल होता है और न ही परिवहन विभाग के कोई नियम लागू होते है

आपको जो भी कार्य कराना हो आप दलाल को मोटी रकम दीजिए और मन चाहा कार्य आरटीओ कार्यालय से करवा लीजिए फिर चाहे आपको ड्राइविंग आती हो या नहीं आपका लाइसेंस जरूर बन जायेगा ।। नए परिवहन अधिकारी के आने से अनुपपुर की जनता खुश थी की ये यहाँ कुछ बदलाव करेंगे परंतु ये भी उसी सिस्टम का अनुसरण करते नजर आ रहे है जय हो अनुपपुर और अनुपपुर जिले के अधिकारी जब जिसकी मौका मिला कर दी गरीबों की जेब खाली।

## स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला खेल परिसर अनूपपुर की सफाई खिलाड़ियों ने ग्राउंड से गाजर घास की सफाई की और लम्बी कूद के लिए मैदान तैयार किया

**यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ** अनुपपुर, स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जिला खेल परिसर अनुपपुर में खिलाड़ियों और अधिकारियों द्वारा सफाई अभियान का आयोजन किया गया। कलेक्टर हर्षल पंचोली, पुलिस अधीक्षक सीटी उर रहमान, जिला पंचायत सीईओ तन्मय वशिष्ठ शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और प्रभारी जिला खेल अधिकारी इसरार मन्सूरी के मार्गदर्शन में इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। खिलाड़ियों ने मैदान में गाजर घास

की सफाई की और लम्बी कूद प्रतियोगिता के लिए मैदान को तैयार किया। इस पहल का उद्देश्य खेल मैदान को बेहतर और स्वच्छ बनाना था ताकि खिलाड़ियों को अनुकूल वातावरण में अभ्यास का मौका मिल सके। सामूहिक प्रयास से मैदान को साफ-सुथरा किया गया, जिससे मैदान अब लम्बी कूद और अन्य खेलों के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। इस सफाई अभियान के बाद पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव के प्रिय वृक्ष समी का पौधारोपण किया गया। समी का पौधा धार्मिक और



सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसके रोपण का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरा-भरा वातावरण तैयार करना था। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी श्री पूरन सिंह श्याम को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष चैतन्य मिश्रा, संरक्षक पंकज अग्रवाल, मैकल बैडमिंटन क्लब के अध्यक्ष अशुतोष त्रिपाठी, सचिव रहीश खान, यातायात विभाग से जितेंद्र नरबदिया, रामधनी तिवारी, भगवा पार्टी के जिला महामंत्री वरुण

चटर्जी और वरिष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी मो. नईम मंसूरी और एहशानुल हक सहित कई अन्य प्रमुख लोग शामिल रहे। कार्यक्रम का आयोजन रामचन्द्र यादव जिला खेल प्रशिक्षक खेल एवं युवा कल्याण विभाग अनुपपुर द्वारा किया गया जिसमें खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए मैदान को साफ किया और टीम भावना का परिचय दिया। स्थानीय लोगों ने इस अभियान की सराहना की और इसे सामुदायिक विकास और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया।



## जयंत चौधरी ने मीरापुर उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का मन टटोला

(सुरेंद्र सिंघल)  
मुजफ्फरनगर (मीरापुर), मीरापुर विधानसभा सीट का उपचुनाव राष्ट्रीय लोकदल के लिए इतना अहम है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि पिछले तीन दिनों के भीतर रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने क्षेत्र के दो दौरे किए। 22 को उन्होंने मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के रामराज में कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी और 24 सितंबर को उन्होंने बिजनौर में आयोजित कौशल महोत्सव में भाग लिया। जहां उन्होंने 3500 युवाओं को जोब आफर लेटर सौंपे। क्षेत्रीय रालोद सांसद चंदन चौहान ने नेतृत्व में हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभारी जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह दोनों की इच्छा थी कि ग्रामीण भारत की प्रतिभाओं को सम्मान और रोजगार का उचित मंच मिले। उनके मंत्री बनने के बाद स्थितियों में बड़ा बदलाव यह आया है कि पहले युवा नोएडा, गुडगांव और दिल्ली



में बड़ी कंपनियों के चक्कर लगाते थे लेकिन अब ये कंपनियां उनके पास खुद चलकर आ रही हैं। बतौर शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि वर्ष 2014 में शिक्षा पर मात्र 68 हजार करोड़ रूपया खर्च होता था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल के बाद आज बढ़कर एक लाख 30 हजार करोड़ पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद तीन हजार राजकीय आईटीआई हैं। जिनके सुधार के लिए 1 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान बजट में किया गया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा

युवा भारत और वर्तमान का भविष्य है। जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि एनडीए सभी दस सीटों पर चुनाव लड़ेगा। मीरापुर सीट पर रालोद दमदार और जीत की संभावनाओं वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ाएंगी। जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ों को लेकर अखिलेश द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर कहा कि पुलिस मुठभेड़ एक प्रक्रिया है जब तक उसकी जांच सामने नहीं आ जाती है तब तक उस पर कोई प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं होगा।

## सेंट्रल बैंक में ताला तोड़कर घुसे चोर सीसीटीवी व अलार्म सिस्टम को बनाया निशाना



**यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ**  
। अनूपपुर, जिले के करन पठार थाना अन्तर्गत ग्राम तुलरा में मंगलवार-बुधवार की रात्रि दो चोरों ने बैंक का ताला तोड़ते हुए वाहन चोरी करने का प्रयास किया। ताला तोड़ने के साथ वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरा को भी उन्होंने तोड़ दिया साथ ही अलार्म सिस्टम को भी तोड़ने का प्रयास

किया। बैंक के सर्विलांस सिस्टम से जानकारी सुरक्षा एजेंसी को होने पर सुरक्षा एजेंसी ने पुलिस और बैंक प्रबंधन को इसकी सूचना दी। रात्रि लगभग 3 बजे पुलिस और बैंक का स्टाफ मौके पर पहुंचा लेकिन तब तक चोर फरार हो चुके थे। दो आरोपी रैनकोट पहने और चेहरा ढंककर बैंक परिसर में पहुंचे, चारों ने पहले बैंक के बाहर

लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा। इसके बाद ताले को तोड़ते हुए बैंक के भीतर प्रवेश करने के साथ ही वहां लगे हुए अलार्म सिस्टम को तोड़ने का प्रयास किया। साथ ही कैश काउंटर के दराज खोलकर उन्हें चेक किया लेकिन वह खाली निकाला वहीं पकड़े जाने के डर से मौके से फरार हो गए।  
**डांग स्कायड, फिंगर प्रिंट टीम मौके पर करन पठार थाना प्रभारी संजय खलको ने बताया कि मंगलवार- बुधवार की रात्रि लगभग 3 बजे मामले की सूचना मिली। मौके पर पहुंच कर देखा तो बैंक का ताला टूटा हुआ था लेकिन आरोपित वहां से फरार हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज देखने पर दो लोग दिखाई पड़ रहे हैं। घटना की सूचना के पश्चात शहडोल से फोरेंसिक एक्सपर्ट एवं डांग स्कायड सुबह मौके पर पहुंच कर जांच कर रहीं हैं। ज्ञात हो कि बैंक किराए के एक मकान में संचालित है जहां समीप ही किराएदार भी रहते हैं। रात्रि में बैंक में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं रहती। रात्रि में सुरक्षा की**

व्यवस्था न होने से सूनेपन का फायदा उठाते हुए चोरों ने इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज तथा मौके पर की गई जांच के आधार पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने के साथ ही उनकी तलाश कर रही है।  
**पहले भी हुआ था असफल प्रयास सेंट्रल बैंक शाखा बेनीबारी तथा बिजुरी कालरी में भी चोरी का प्रयास हो चुका है। जहां दोनों ही स्थान पर कर कुछ भी समान नहीं ले जा सके। वहीं इसी शाखा 8 वर्ष पूर्व भी चोरी का असफल प्रयास हो चुका है। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी बैंक प्रबंधकों की बैठक ली थी जिस पर सुरक्षा के पुख्सार व्यवस्था के निर्देश दिये थे साथ ही बिजुरी में सेंट्रल बैंक का संचालन जर्जर भवन में होने पर भवन को बदलने की बात कही थी। पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने बताया कि संदिग्धों की तलाश की जा रही है, जल्द ही चोरो को पकड़ा जाएगा**

## विकास चेतना सप्ताह शुरू



**भगवान दास बेरागी । सिटी चीफ** शाजापुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शाजापुर इकाई द्वारा एसएफडी का विकास चेतना सप्ताह की शुरुआत बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाकर की गई। इस दौरान विद्यार्थी परिषद की भूमिका जिला प्रमुख प्रतीक शर्मा के द्वारा बताई गई। वहीं सुभित राठौर ने जल, जंगल, जीव, जंतु के संरक्षण पर किए जाने वाले कार्य के बारे में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को बताया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस के प्राचार्य डॉ विद्याशंकर विमूति मौजूद रहे।

**राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस के अवसर पर गोष्ठी हुई आयोजित**  
छात्रों ने कालेज परिसर में साफ-सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया



**गौरव सिंघल । सिटी चीफ**  
देवबंद (सहारनपुर), राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय बताया गया। इस दौरान स्वयं सेवियों ने सफाई अभियान चलाया। गोष्ठी में प्राचार्य डा. अतुल शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और चरित्र का

विकास कर राष्ट्रीय सेवा के लिए जागरूक करना है। इससे पूर्व सेवा अभियान के तहत छात्रों ने कालेज परिसर में साफ-सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। शिविरार्थियों ने राष्ट्रीय सेवा योजना के गीत प्रस्तुत कर शपथ ली और स्वच्छ रहने का प्रण किया। संचालन डा. टीना ने किया। इस अवसर पर डा. कुसुम लता, डा. मोहम्मद आरिफ, डा. विनीत, राजीव, लोकेश कुमार शर्मा, प्रमोद कुमार आदि मौजूद रहे।

## ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित वैश्विक व्यापार महाकुंभ में जामिया रेमेडीज देवबंद की ओर से स्टॉल लगाया गया

## उद्घाटन राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने फीता काटकर किया

**गौरव सिंघल । सिटी चीफ**

नोएडा/देवबंद, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित वैश्विक व्यापार महाकुंभ में जामिया रेमेडीज देवबंद की ओर से स्टॉल लगाया गया। जिसका उद्घाटन राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को तरक्की के नए आयाम दिए हैं। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में 25 सितंबर से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2024 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में किया। इस महाकुंभ में जामिया रेमेडीज देवबंद की ओर से स्टॉल



लगाकर भागीदारी की गई। स्टॉल का उद्घाटन करते हुए राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश दिन प्रति दिन हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। उन्होंने ने कहा 2011 से मोदी

योगी की सरकार में सबसे ज्यादा रोजगार नौजवान को मिल रहा है। उन्होंने कहा की मोदी सरकार ने आयुष मंत्रालय की तरक्की के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जिससे आयुष पद्धति को दिन प्रति दिन बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने

जामिया रेमेडीज देवबंद की टीम को बधाई देते हुए कहा कि वैश्विक व्यापार महाकुंभ में जामिया रेमेडीज के स्टॉल लगाने से क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। जामिया रेमिडिज के डायरेक्टर डॉ. अख्तर सईद ने कहा की यह हमारा

## मोबाइल देखने का प्रचलन मानसिक रोग का कारण: विधायक देवेंद्र निम

एकल परिवार के चलते बढ़ रहे हैं मानसिक रोग के मरीज – सीएमओ

**गौरव सिंघल । सिटी चीफ**

नागल। सहारनपुर, सीएचसी में लगे मानसिक स्वास्थ्य शिविर का क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र निम ने फीता काटकर शुभारंभ करते हुए कहा कि वर्तमान समय में व्यस्त जीवन शैली व कार्य का बोझ तथा बच्चों में मोबाइल देखने का प्रचलन मानसिक रोग का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में सरकार द्वारा संचालित अनेकों योजनाओं से हम वंचित रह जाते हैं। कुछ गम्भीर मरीजों की प्रतिपुर्ति आयुष्मान कार्ड से नहीं हो पाती व मरीज सम्बंधित चिकित्सक से व्यय का



इस्टीमेट बनवाकर सम्बंधित विधायक से व्यय प्रमाणित कर स्वास्थ्य सेवा का

लाभ ले सकते हैं। सीएमओ डॉ प्रवीण कुमार ने कहा कि आज सोशल मीडिया

का अत्यधिक प्रचलन, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति व एकल परिवार के कारण मानसिक रोगों के मरीज बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र निम ने आंगनवाड़ी विभाग द्वारा आठ गर्भवती माताओं की गोद भराई की। इस दौरान पपिन चौधरी, मा इन्देश त्यागी, हरीश त्यागी, अरुण त्यागी, व्यापार मण्डल अध्यक्ष कपिल डाबर, राजकुमार चौधरी, संजय चैयरमैन, ब्रह्म सिंह, डॉ ख्वाजा खय्याम, अंशिका, सूरज सिंह, मुदस्सर अली, डॉ ईशा जैन, डॉ आशा चौहान, कमल सिंह राणा आदि मौजूद रहे।

# ग्राम उदयपुर में अंत्योदय दिवस का आयोजन हुआ

200 हितग्राहियों की स्वास्थ्य जांच सहित रक्तचाप शुगर, बीपी सहित अन्य जांचे हुई, 65 आयुष्मान कार्ड बनाए

**विदिशा**  
**स्वच्छता ही सेवा अभियान तहत स्वच्छता की शपथ दिलाई**

नीति आयोग भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार आकांक्षी विकास खण्ड बासौदा के ग्राम उदयपुर के महामाया मंदिर परिसर में अंत्योदय दिवस का आयोजन विधायक श्री हरि सिंह सप्रे के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। विधायक श्री हरिसिंह सप्रे द्वारा स्वभाव ही स्वच्छता कार्यक्रम अंतर्गत लोगों को अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का बोध कराते हुये कहा कि हमें अपने आसपास की साफ-सफाई के लिए स्वयं आगे आना होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सहरिया समुदाय परिवारों के सदस्यों के साथ अन्य ग्रामीणजनों ने सहभागिता की

एवं सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, 200 हितग्राहियों की स्वास्थ्य जांच की गई, 65 आयुष्मान कार्ड, पी.व्ही.टी.जी परिवारों के 16 आयुष्मान कार्ड बनाये गये, 115 व्यक्तियों की रक्तचाप एवं शुगर की जांच, 115 लोगों टीबी की जांच, मौके पर 11 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिसमें 2 गर्भवती हाई रिस्क पाई गई, जिन्हें उचित उपचार प्रदाय किया गया। आरबीएसके 18 एवं 25 लोगों की आंखों की जांच की गई, जिनमें 10 चश्मे प्रदाय किये गये। शिविर मे मौके पर ही मंच से विभिन्न विभागीय हितग्राही मूलक योजनाओं का हितलाभ वितरण किया गया। जिसमें कृषि विभाग के द्वारा 8 स्वाइल हेल्थ कार्ड, 5 आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा

एवं स्वच्छता जागरूता के लिए नुकड-नाटक मंचन किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छत भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 06 स्वच्छता मित्रों को स्वच्छता किट एवं डिजिटलि कार्ड का वितरण कर सम्मानित किया गया। वहीं 03 परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया एवं पीएम जनमन आवास योजना अंतर्गत 15 पीव्हीजीटी हितग्राहियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण किया गया, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 03 कुपोषित बच्चों के सुपोषित होने पर उन्हें उपहार प्रदान किया गया। आजीविका मिशन योजना अंतर्गत 2 महिलाओं को सीसीएल की राशि का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर डॉ. राकेश सिंह जादौन, श्री कैलाश रघुवंशी, श्रीमति नीतू देवेन्द्र रघुवंशी, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य श्री पंकज एलिया



एवं श्रीमति गायत्री नरेंद्र रघुवंशी, क्षेत्रीय जनपद सदस्य श्रीमति पूजा मोंगिया, ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमति वर्षा राजेन्द्र चैरसिया, श्री पंकज जैन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, श्री विजय राय,

अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा एवं जिला एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिक एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हितग्राहियों की उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन

डॉ. पी.के. मिश्रा आकांक्षी जिला समन्वयक के द्वारा तथा कार्यक्रम का आभार श्री भगवानसिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसौदा द्वारा व्यक्त किया गया।



कृषि कानून वापस लिए जाने संबंधी बयान से हरियाणा में हो सकता था नुकसान

## भाजपा के लिए सिरदर्द बनते जा रहे सांसद कंगना रनौत के बयान

**नई दिल्ली।** हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत के बयान बीजेपी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। कुछ ही समय में कंगना ने ऐसे दो बयान दिए हैं, जिससे बीजेपी ने तुरंत किनारा कर लिया। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि वह बीजेपी की ओर से बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। पहले किसान आंदोलन और फिर अब तीनों कृषि कानूनों को लेकर कंगना ने जो कहा है, उससे पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ सुर्त उठने लगे हैं। कृषि कानूनों को लेकर कंगना रनौत ने पहले कहा कि मुझे पता है कि विवाद होगा, लेकिन मुझे लगता है कि निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को भी इसकी मांग करनी चाहिए। हालांकि, विवाद बढ़ने पर कंगना ने खेद जताते हुए अपने शब्दों को वापस ले लिया। कंगना के बयान से बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में नुकसान होने की संभावना जताई जा रही थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के



लिए पांच अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर वोटिंग है, जिसके नतीजे आठ अक्टूबर को आएंगे। राज्य में पिछले एक दशक से बीजेपी की सरकार होने से पार्टी को पहले से ही एंटी इनकमबेंसी का सामना करना पड़ रहा है। अग्निवीर, किसान संबंधी मुद्दे, बेरोजगारी आदि को लेकर राज्य की जनता में बीजेपी सरकार के खिलाफ कई बार नाराजगी भी देखी गई है। वहीं, टिकट कटने की वजह से बीजेपी कई नेताओं की बगावत भी झेल रही। ऐसे में चुनावी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कंगना के

तीनों कृषि कानूनों को वापस लाने की मांग करने वाला बयान हरियाणा में बीजेपी को और नुकसान पहुंचा सकता था। यही देखते हुए बीजेपी ने कंगना के बयान का खंडन करते हुए कहा कि यह उनका निजी बयान है। कुछ साल पहले दिल्ली की सीमाओं पर हुए किसान आंदोलन के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा के भी बड़ी संख्या में किसान आंदोलन के लिए लंबे समय तक बैठे थे। इसके बाद पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था।

### कंगना पर राहुल का पलटवार, कहा- सरकार की नीति कौन तय कर रहा, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी?

**नई दिल्ली।** भाजपा सांसद कंगना रनौत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है। कंगना के वापस लिए जा चुके कृषि कानूनों की वापसी की वकालत करने वाले बयान पर राहुल ने कहा कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है? एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? 700 से ज्यादा किसानों, खास कर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत ले कर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। हमारा गठबंधन (आईएनडीआईए) हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई भी षडयंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो प्रधानमंत्री को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस ने रनौत की तीन कृषि कानूनों को वापस लाने की मांग वाली टिप्पणी को लेकर भाजपा पर हमला तेज कर दिया। पार्टी ने मांग की कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी उनकी टिप्पणियों से सहमत नहीं है तो अभिनेत्री-राजनेता को पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सहित चुनावी राज्य सत्तारूढ़ पार्टी को करारा जवाब देगे।

## शक्तिशाली भूकंप के बाद अब जापान में सुनामी का खतरा

**टोकियो।** जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने शक्तिशाली भूकंप के बाद टोकियो के दक्षिण में दूरदराज के द्वीप समूह के लिए सुनामी संबंधी चेतावनी जारी की। सुदूरवर्ती समुद्र तट पर आए इस भूकंप के कारण जान-माल के नुकसान की अभी कोई सूचना नहीं मिली है। मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि झुजु द्वीप के तटीय इलाके में मंगलवार सुबह 5.9 तीव्रता का भूकंप आया और कुछ ही मिनट बाद क्षेत्र में एक मीटर ऊंची लहरें उठने लगीं। एजेंसी ने कहा कि अपतटीय भूकंप हचिजो द्वीप से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण में आया, जो तोक्यो से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में है। जापान के एनएचके सरकारी टेलीविजन चैनल के अनुसार, हचिजो द्वीप के निवासियों ने बताया कि उन्हें भूकंप महसूस नहीं हुआ और उन्होंने केवल सुनामी की चेतावनी सुनी। जापान रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यह प्रशांत महासागर का ऐसा इलाका है जहां भूकंप आने का खतरा अधिक रहता है।

### वैष्णोदेवी : 2 अक्टूबर से चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

**नई दिल्ली।** माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने उदयपुर सिटी से श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा तक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। यह ट्रेन सेवा 2 अक्टूबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक चलेगी, जिसमें कुल 7 ट्रिप होगी। गाड़ी संख्या 09603, उदयपुर सिटी से हर बुधवार को दोपहर 01-50 बजे रवाना होगी और अगले दिन गुरुवार को सुबह 06-35 बजे श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 09604, श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा से हर गुरुवार सुबह 10-50 बजे रवाना होकर शुक्रवार को दोपहर 13-55 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी। इस ट्रेन का रूट कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगा, जिनमें राणाप्रतापनगर, मावली, चंदेरिया, भीलवाड़ा, अजमेर, लुधियाना, जालंधर कैंट, और जम्मूतवी सहित कुल 21 स्टेशनों पर स्टॉपेज होंगे। ट्रेन में 2 सेकंड एसी, 6 थर्ड एसी, 2 थर्ड एसी इकोनॉमी, 5 स्लीपर क्लास और 4 सामान्य कोच होंगे, जिससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। त्योहारों के दौरान वैष्णो देवी की यात्रा को और भी सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए यह स्पेशल ट्रेन एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी।

40 डिग्री में भी गर्म रहेंगे ये टेंट, ड्रोन अटैक को फेल करेगी गन,भारतीय सेना ने फॉरवर्ड एरिया में तैनाती के लिए खरीदे 100 रोबोटिक म्यूल्स

## वजन ढोने के साथ दुश्मन पर गोलियों की बौछार भी कर सकता है रोबो खच्चर

**नई दिल्ली।** भारतीय सेना ने फॉरवर्ड एरिया में तैनाती के लिए 100 रोबोटिक म्यूल्स (रोबो खच्चर) खरीदे हैं। ये वजन ढोने के साथ जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर गोलियों की बौछार भी कर सकते हैं। सेना ने यह खरीद इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत की है। इसके अलावा सेना सियाचिन जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में तैनात जवानों के लिए -40 डिग्री तापमान को भी सहने वाले नए टेंटों को खरीदने की भी योजना बना रही है। इन टेंटों का हाई एल्टीट्यूड इलाकों में ट्रायल भी चल रहा है और अभी तक ये उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। इसके अलावा जिस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है और ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग्स की तस्करी को अंजाम दिया रहा है, ऐसे में सेना एंटी-ड्रोन सिस्टम की भी तलाश कर रही है, ताकि दुश्मन की तरफ से छोड़े जाने वाले ड्रोनों को जाम किया जा सके। सेना की एक यूनिट को ये गन सप्लाई भी की गई हैं। भारतीय सेना हाई एल्टीट्यूड इलाकों में इस्तेमाल के लिए जिन प्रोडक्ट्स में रूचि दिखा रही है, ये सभी प्रोडक्ट्स पिछले सप्ताह लेह में आयोजित हिमटेक सिंपोजियम में प्रदर्शित किए गए। हिमटेक सिंपोजियम

में लोगों में आकर्षण का केंद्र बने रोबोटिक म्यूल यानी रोबोटिक खच्चर को किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह न केवल वजन ढो सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर गोलियों की बौछार भी कर सकता है। भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद (ईपी) के चौथे चरण (सितंबर 2022 से सितंबर 2023) के तहत 100 रोबोटिक खच्चर खरीदे हैं और उनकी फॉरवर्ड एरिया में तैनाती की योजना है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ 2020 के गतिरोध के बाद से, सेना कई तरह के कार्यों के लिए विशेष रूप से हाई एल्टीट्यूड इलाकों के लिए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की तलाश कर रही है। रोबोटिक म्यूल को बनाने वाले कंपनी एयरोआर्क के प्रबंध निदेशक और सीईओ अर्जुन अग्रवाल ने अमर उजाला को बताया कि उनका बनाया रोबोटिक म्यूल सभी प्रकार की बाधाओं और रुकावटों को पार कर सकता है। वह पानी के अंदर जा सकता है और नदी-नालों को भी पार कर सकता है। उसके पास इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स, इंफ्रारेड जैसी चीजों को पहचानने की क्षमता है। यह न केवल सीढ़ियां, खड़ी पहाड़ियों और अन्य बाधाएं आसानी से पार कर सकता है,



बल्कि -40 से +55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी काम कर सकता है। साथ ही, यह 15 किलोग्राम का वजन भी ढो सकता है। वहीं भारतीय सेना लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड इलाकों में भी तैनात है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। सर्दियों में यहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियक तक भी पहुंच जाता है। भारतीय सेना को इन इलाकों में तैनात अपने जवानों के लिए एल्टीट्यूड इलाकों में तैनात जवानों के लिए खास टेंट तैयार किए हैं, जिन्हें पीक पॉइंस कहा जाता है। इन्हें शून्य से भी नीचे के तापमान वाले इलाकों के लिए जैसे सियाचिन में भी तैनात है। डीटेक 360 इनोवेशन के

## बदलापुर एनकाउंटर पर उच्च न्यायालय ने उठाए सवाल, हाईकोर्ट ने कहा- एक कमजोर आदमी फायर नहीं कर सकता, पुलिस ने आरोपी के सिर में गोली क्यों मारी? गड़बड़ी तो लग रही, निष्पक्ष जांच जरूरी

**मुंबई।** बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे उच्च न्यायलय ने सवाल उठाए हैं। उच्च न्यायालय ने बुधवार को बदलापुर मामले के आरोपी अक्षय शिंदे के पिता की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान उच्च न्यायालय ने पुलिस कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठाए। उच्च न्यायालय ने पूछा कि पुलिस ने पिस्टल अनलॉक क्यों की थी? हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि एक शारीरिक रूप से कमजोर आदमी तेजी से रिवॉल्वर को अनलॉक करके फायर नहीं कर सकता। यह आसान नहीं है। इस पर सरकारी वकील ने बताया कि अधिकारी की पिस्टल पहले से अनलॉक थी। याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ के जस्टिस चौहान ने कहा कि बताई जा रही बातों पर यकीन करना बेवद मुश्किल है। प्रथम दृष्टया इसमें गड़बड़ी नजर आ रही



है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस ने आरोपी के सिर में गोली क्यों मारी? आरोपी को गोली मारने से बचा जा सकता था। आरोपी को गोली मारने से पहले काबू में करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी अक्षय शिंदे की मौत की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए। अक्षय शिंदे के पिता ने उच्च न्यायालय में

याचिका दायर कर अपने बेटे की मौत की जांच एसआईटी से कराने की मांग की है। पिता का आरोप है कि उनके बेटे को फर्जी एनकाउंटर के तहत मारा गया है। विपक्षी पार्टियां भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रही हैं। एनकाउंटर पर सवाल उठने और सियासत गरमाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को घटना की जांच सीआईडी को सौंप दी है। याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति

रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने की। बच्चियों के यौन शोषण का आरोपी था अक्षय शिंदे अक्षय पर बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों का यौन शोषण करने का आरोप था। साथ ही उस पर अपनी पूर्व पत्नी के भी यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज था। पूर्व पत्नी के यौन उत्पीड़न के मामले में ही पुलिस उसे जांच के लिए तलोजा जेल से बदलापुर लेकर गई थी। सरकार का कहना है कि जांच के बाद जेल लौटते समय अक्षय ने एक पुलिस अधिकारी की रिवॉल्वर छीनकर पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर तीन गोलियां चलाईं। जिनमें से एक गोली अस्मिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे की जांच में लगी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अक्षय के सिर में गोली लगी और उसकी मौत हो गई।

बदलापुर एनकाउंटर का उट शिंदे ने किया बचाव, बोले- आरोपी भाग जाता तो विपक्ष कहता हमने भगाया

**मुंबई।** बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट के कड़े सवाल उठाए जाने के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुलिस का बचाव किया है। शिंदे ने बुधवार को एक कार्यक्रम में मुंबई पुलिस के एनकाउंटर का बचाव करते हुए कहा कि अगर आरोपी भाग जाता तो विपक्ष कहता कि हमने भगाया। मुख्यमंत्री शिंदे ने विपक्ष पर मामले में पॉलिटिक्स और पाखंड करने का आरोप लगाया। शिंदे ने बदलापुर एनकाउंटर पर कहा, पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। अगर वह (आरोपी) भाग जाता तो विपक्ष कहता कि बंदूक दिखावे के लिए नहीं थी। वे कहते कि हमने उसे भागने पर मजबूर किया। मुठभेड़ में पुलिसकर्मों घायल हो गए। हमें पुलिस का समर्थन करना चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में शक्तिशाली देशों की लिस्ट में 5 पायदान लुढ़का, चीन दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर

## यूक्रेन युद्ध में खस्ताहाल हुआ रूस!

**नई दिल्ली।** पिछले ढाई साल से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस दौरान रूस पश्चिमी देशों के कई तरह के प्रतिबंध झेल रहा है, जिसमें आर्थिक प्रतिबंध भी शामिल हैं। इन वजहों से रूस की हालत खस्ता हुई है, जबकि वह दुनिया का दूसरा शक्तिशाली देश माना जाता रहा है। ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने हाल ही में नवीनतम एशियन पावर इंडेक्स प्रकाशित किया है। इसमें रूस पांच पायदान नीचे लुढ़क गया है। माना जा रहा है कि रूस ने पिछले दो सालों में सैन्य शक्ति मजबूत करने के लिए रक्षा क्षेत्र पर अधिक खर्च किया है और इस कोशिश में कई पैमानों पर पिछड़ गया है। इन्स्टीट्यूट ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में 27 देशों की तुलना की है। इनमें 131 संकेतकों और आठ मानदंडों पर गौर किया गया है। इसमें पाया गया है कि रूस एशिया पावर इंडेक्स 2024 में एक स्थान नीचे खिसक गया है, उसे 100 में से 31 अंक मिले हैं, जो कुल मिलाकर 0.4 अंकों की गिरावट है। इससे पहले 2023 में



रूस चार अंक नीचे खिसका था। 2024 की लिस्ट में अब रूस छठे पायदान पर है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गिरावट दर्ज करने वाले बड़े तीन देशों में एक रूस भी शामिल है। रूस के अलावा जापान और पाकिस्तान भी एक-एक अंक नीचे लुढ़का है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन के खिलाफ अपने आक्रमण को मजबूत करने के लिए युद्ध अर्थव्यवस्था को

संगठित करने के कारण रूस की सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई है लेकिन आठ में से पांच मेट्रिक्स के स्कोर में कमी आई है। इन पांच मानदंडों में सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक योग्यता, लचीलापन, आर्थिक संबंध और रक्षा नेटवर्क शामिल हैं। रिपोर्ट में शक्तिशाली देशों की लिस्ट में अमेरिका अभी भी नंबर वन बना हुआ है, जबकि चीन दूसरे और छलांग लगाते हुए भारत तीसरे

पायदान पर पहुंच गया है। पिछले साल की तुलना में भारत ने एक अंक की छलांग लगाई है, जबकि अमेरिका और चीन अपनी-अपनी जगहों पर कायम हैं। इससे उलट जापान और रूस एक-एक अंक की कमी के साथ लिस्ट में क्रमशः चौथे और छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। आस्ट्रेलिया ने भी एक अंक की छलांग के साथ पाँचवाँ स्थान हासिल किया है।

उनके प्रोडक्ट्स का लेह (11,500 फीट), दौलत बेग ओरखी (16,700 फीट) और दुरबुक (12,500 फीट) पर भी ट्रायल किया जा चुका है। लेह में ट्रायल दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक और दुरबुक में दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 तक आयोजित किए गए थे। जबकि डीबीओ में मई 2023 में शुरू हुए परीक्षण अभी भी जारी हैं। हिमटेक में आए सेना के वरिष्ठ अफसरों ने भी पीक पॉइंस के रिजल्ट्स की काफी तारीफें कीं और कहा कि ये उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। मित्तल ने बताया कि पीक पॉइंड को तेजी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसे 30 किलोग्राम के ब्लॉकों में तोड़ा जा सकता है और यह उच्च ऊंचाई वाले सैन्य ठिकानों, अंतर्राष्ट्रिका जैसे रिसर्च स्टेशनों, फास्ट-ट्रैक अस्पतालों और बतौर आपदा राहत शिविर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

भारतीय सेना को मिली स्वदेशी एंटी ड्रोन गन वहीं रूस-यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हमलों के लिए हो रहा है, उससे भारतीय सेना भी निर्विंत है। पहले ही पाकिस्तान से सटे पंजाब के बॉर्डर इलाकों में जिस तरह से ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की खेप की

डिग्री की एक अदृश्य बीम निकलती है, जो एक जाल की तरह ड्रोन को घेर लेती है और ड्रोन का कंट्रोल खत्म हो जाता है और वह जाम हो जाता है। इसमें कई तरह की फ्रिक्वेंसी दी गई हैं। इस गन को मोबाइल की तरह ही चार्ज किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह स्वामं ड्रोनों को भी मार गिरा सकती है, इसके लिए यह मदर स्वामं ड्रोन पर टारगेट करती है, जिससे बाकी ड्रोन को भी सिग्नल नहीं मिलता और धीरे-धीरे उनकी बैटरी डाउन हो जाती है और वे नीचे गिर जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह एंटी ड्रोन सिस्टम इस तरह से तैयार किया गया है कि पैदल सैनिक भी 15 हजार से लेकर 18 हजार फीट पर बनीं पोस्टों तक इसे आसानी से उठा कर ले जा सकते हैं। गौरव के मुताबिक रक्षा मंत्रालय-ऊए प्रोग्राम के तहत स्टार्टअप को प्रोटीटाइप बनाने के लिए फंड देता है, ताकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जरूरतें स्वदेशी कंपनियां पूरी कर सकें। सेनाओं की जरूरतों के मुताबिक अगर स्टार्टअप ने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है, तो प्रोटीटाइप के लिए मंत्रालय मदद करता है और फिर उस प्रॉडक्ट को सेनाओं के लिए खरीदा जाता है।